शनिवार
12 सितंबर -2026
वर्ष 11, अंक 04
पेज 8, मूल्य 2 रुपए
रांची

रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

अलग पहचान

सत्य की उड़ान

पेज-8

संक्षिप्त समाचार

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से भारतीय युवा निराशः राहुल

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पीढ़ी को निराश कर रही है, जिसे बेहतर भविष्य देने के लिए बनाया गया था। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से पूछा कि उनका शिक्षा व्यवस्था से भरोसा क्यों उठ गया है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की शुरुआत उन लोगों की बात सुनने से होगी, जो रोजाना इसकी कमियों का सामना कर रहे हैं। राहुल ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपने अनुभव, सबूत और सुझाव ऑनलाइन साझा करने को कहा। राहुल ने यह बात छात्रों की गूंज के 8 दिन पहले की है। इसका आयोजन 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। अब तक तक कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में 4 कार्यक्रम कर चुके हैं।

शुभेंदु ने मंदिर में बैठकर खाई मछली

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट के मां काली मंदिर में बैठकर मछली खाई, जिससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा बागेश्वर के दुर्गापूजा में नॉन-वेज न खाने वाले विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री ने दुर्गा पूजा के दौरान बंगालियों से दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहार छोड़ने की अपील की थी। वहीं धार्मिक मौकों पर मांस खाने वालों को ढोंगी बताया था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही बाबा बागेश्वर की इस बात को खारिज किया था, लेकिन ये विवाद थम नहीं रहा था। अब शुभेंदु अधिकारी कालीघाट पहुंचे और उन्होंने मंदिर में बैठकर मछली का भोग खाया।

यूपी की 681 सड़कें होंगी गड्ढामुक्त

अस्पतालों और बाजारों की सड़के प्राथमिकता पर सुधारें

लखनऊ (एजेंसी)। बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों को अब तत्काल आवागमन योग्य बनाया जाएगा। बरसात अभी जारी रहने के कारण फिलहाल क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर उन्हें मोटरेबल किया जाएगा, जबकि बारिश खत्म होने के बाद उसे सुधारा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को सड़कों की स्थिति पर लगातार नजर रखने और बारिश से नए क्षतिग्रस्त मार्गों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा।

तमिलनाडु के मंदिरों में अब लागू होगी नई व्यवस्था

● मंदिरों के प्रसाद की क्वालिटी और कीमत होगी तय ● थलपति विजय की सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की गुणवत्ता, मात्रा और कीमत को लेकर थलपति विजय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।। प्रसाद को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने 10 तरह के आम प्रसाद के लिए एक मास्टर स्कीम तैयार की है। इसके तहत पूरे राज्य में भक्तों को तय मानक के अनुसार प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था में प्रसाद की रेसिपी, सामग्री का अनुपात, मात्रा, बैच साइज, कीमत और पैकेजिंग का मानक तय किया जाएगा। मंदिरों को प्रसाद परिसर में ही तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के मुताबिक, प्रसाद की गुणवत्ता और बनाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए इसे बाहर से बनवाने की व्यवस्था को हतोत्साहित किया जाएगा। विभाग कमिश्नर टीजी विनय के सर्कुलर के मुताबिक, प्रसाद तैयार करने में आविन घी और कोऑपरेटिव स्टोर की दरों पर खरीदी गई सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रसाद की कीमत कच्चे माल, एलपीजी, श्रम और पैकेजिंग की लागत को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। इसके तहत 50 ग्राम लड्डू की बिक्री कीमत 20 रुपये तय की गई है।

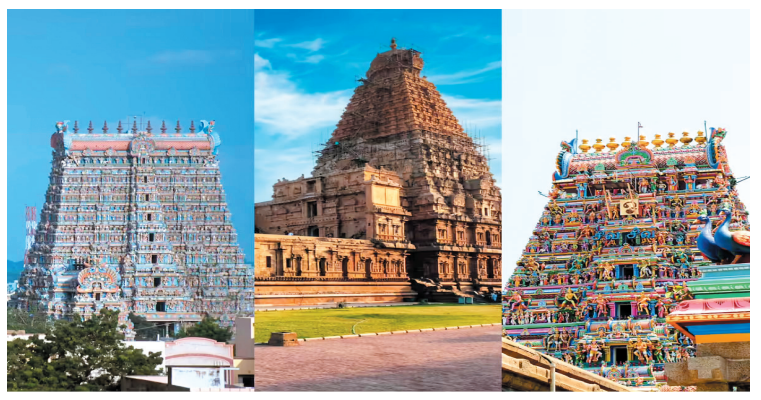

पैकेजिंग पर देनी होगी पूरी जानकारी

प्रसाद की पैकेजिंग को लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 के नियम 27 के अनुरूप रखना होगा। पैकेट पर निर्माता या आयातक का नाम-पता, उत्पाद का सामान्य नाम, कुल मात्रा, निर्माण या पैकिंग की तारीख, एमआरपी, यूनिट बिक्री मूल्य और शिकायत के लिए ग्राहक संपर्क की जानकारी दर्ज करनी होगी। बता दें कि कई मंदिरों में प्रसाद बनाने और बेचने का काम बाहरी एजेंसियों को दिया जाता है। ऐसे में इसकी तैयारी और गुणवत्ता पर विभाग का सीधा नियंत्रण नहीं रहता। नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रसाद की गुणवत्ता और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। ऐसे प्रस्ताव संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त या आयुक्त के पास भेजे जा सकेंगे।

'ब्रिक्स' में भाग लेने भारत पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति

पेजेशकियान ने कहा, एकतरफा रवैये का मुकाबला करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कल 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां लगभग-लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब दुनियाभर के नेताओं का आगमन भी लगातार चर्चा में है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तेहरान से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ईरानी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स के मुख्य उद्देश्यों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दुनिया में एकतरफावाद का मुकाबला करना है।

अमेरिकी डॉलर को लेकर भी बोले पेजेशकियान

पेजेशकियान आगे कहा था क ब्रिक्स के भीतर एक विशेष बैंक बनाया गया है और हम देशों के बीच आपसी निवेश को बढ़ावा देने जा रहे हैं ताकि सदस्य देशों के बीच लेन-देन डॉलर पर निर्भरता के बिना हो सके। इससे अमेरिकी डॉलर की मनमानी और आधिपत्य को कम करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं पेजेशकियान ने बताया कि इस सम्मेलन में स्वतंत्रता, एकजुटता, स्थिरता, प्रतिरोध और इनोवेशन जैसे मुद्दों के साथ-साथ आर्थिक, वित्तीय, औद्योगिक और व्यापार से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति ने भारत और ईरान के संबंध को लेकर भी अपना बात रखी।

महाराष्ट्र में ट्रक-बोलेरो भिड़े, 8 लोगों की मौत

जेसीबी-क्रेन से गाड़ी हटाई गई, रायपुर से नागपुर जाते वक्त हादसा

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार को ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 4 बजे नागपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर पिंपलगांव सड़क के पास हुआ। सभी लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर से नेशनल हाईवे-53 के रास्ते नागपुर जा रहे थे। ट्रक में फंसे पिकअप को निकालने के लिए दो जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव का काम शुरू किया। इससे पहले गुरुवार को नांदेड जिले में नांदेड-भोकर रोड पर वैन और ट्रक की टक्कर हो गई थी। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

दुनियाभर का ग्रोथ इंजन है भारत, आईएमएफ ने माना

अबकी जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बेहतर 7.8 फीसदी रही

कहा-ऊर्जा संकट के बावजूद मजबूत रही भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। साथ ही भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन भी बताया है। भारत की अर्थव्यवस्था ने ऊर्जा संकट और वैश्विक चुनौतियों के बीच भी अपनी तेज रफ्तार बरकरार रखी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8 फीसदी दर्ज की गई है। आईएमएफ ने भारत के इस बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मजबूत सर्विसेज सेक्टर और बेहतर एक्सपोर्ट के दम पर यह ग्रोथ उम्मीद से काफी बेहतर रही है। आईएमएफ की प्रवक्ता जूली कोजाक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत की 7.8 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ उनके अनुमान और मार्केट एक्सपर्ट्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। सर्विसेज और एक्सपोर्ट में बेहतर प्रदर्शन ने ग्रोथ बढ़ाई।

आरबीआई के अनुमान से ज्यादा रही विकास दर

पहली तिमाही का यह 7.8 फीसदी का आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 7 फीसदी के पिछले अनुमान से भी ज्यादा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस तिमाही में देश की रियल जीडीपी 81.36 लाख करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 75.46 लाख करोड़ रुपए थी। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी आंकलन की व्यवस्था में किए गए बदलावों और इसके आधुनिकीकरण का स्वागत किया है। जूली कोजाक ने बताया कि नवीनतम डेटा में नया इंडेक्स तैयार है।

ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026

ब्रिक्स में पुतिन का अमेरिका-यूरोप पर तंज, कमजोर देश खुद को जी7 क्यों कहते हैं

● पीएम मोदी बोले- ब्रिक्स देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत जीडीपी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जी7 पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि जी7 को 'ग्रुप ऑफ सेवन' क्यों कहा जाता है।

पुतिन ने कहा कि पिछले 5 साल में दुनिया की 40 प्रतिशत से ज्यादा जीडीपी ब्रिक्स देशों से आई है, जबकि जी7 की हिस्सेदारी सिर्फ 29 प्रतिशत रही। दुनिया की आर्थिक ग्रोथ में भी इसकी हिस्सेदारी आधे से ज्यादा रही, जबकि जी7 का योगदान सिर्फ 18 प्रतिशत रहा।उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह ब्रिक्स देशों की आधी से ज्यादा आबादी और उनके तेजी से बढ़ते घरेलू बाजार हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने भी फोरम को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की आधी आबादी रहती है। ये देश दुनिया की 40 प्रतिशत जीडीपी और 25 प्रतिशत से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा रखते हैं।

शराबकांड के मुख्य आरोपी को पैर में गोली मारकर पकड़ा

● पुलिस पर की 3 राउंड फायरिंग, 31 मौतों के मामले में वॉन्टेड था

सागर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब मामले में शुक्रवार को मुख्य आरोपी रवि लखेरा को पकड़ लिया गया। बरायठा के जंगल में पुलिस और रवि के बीच फायरिंग हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी रवि को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस पर 20 हजार का इनाम था। एसपी अनुराग सुजानिया ने पुष्टि की है। जहरीली शराब पीने से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती 3 और मरीजों ने दम तोड़ा था। हालांकि, प्रशासन 16 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है। इससे पहले प्रशासन ने गुरुवार को 3 आरोपियों के 5 मकानों के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चलाया था। इनमें आरोपी मनीष लोधी, करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राजपूत और आशीष साहू के निर्माण शामिल हैं। वहीं, पुलिस ने अब तक 33 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें रवि लखेरा समेत 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है।

पुलिस पर की 3 राउंड फायरिंग

एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि आरोपी रवि लखेरा की लोकेशन बरायठा के जंगल में यूपी बॉर्डर के पास खैवाहा गांव में मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो रवि अपने दो साथियों के साथ बाइक से भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी की तो रवि ने टीम पर तीन फायर किए, इनमें एक गोली पुलिस की गाड़ी में लगी। चेतावनी के बाद भी नहीं रुकने पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। एक गोली रवि के बाएं पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके दोनों साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

● ब्रिक्स समिट को लेकर कांग्रेस में मचा घमासान

पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम ने पूछा- ब्रिक्स से देश को क्या मिला

थरूर बोले-11 देशों को एक मंच पर लाना भारत की ताकत

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में ब्रिक्स समिट को लेकर कांग्रेस के दो सीनियर नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने पूछा था, 'इस ब्रिक्स से भारत को क्या फायदा हुआ।' उधर, शशि थरूर ने फायदे बताए।

चिदंबरम ने कहा था- इन संगठनों की सदस्यता पर विचार हो

चिदंबरम ने कहा देश को वास्तव में क्या ठोस लाभ मिला है, इस पर विचार होना चाहिए। थरूर ने शनिवार को ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ में 100 से ज्यादा देश हैं, लेकिन ब्रिक्स में शामिल 11 प्रमुख देश दुनिया की बड़ी आबादी और करीब 41 फीसदी वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जासूसी कांड के बाद पाकिस्तान धार्मिक यात्रा के बदले नियम

प्राइवेट टूर पर लगी रोक, वीजा अप्लाई की शर्तें भी बदलीं

हिसार (एजेंसी)। केंद्र और हरियाणा सरकार ने भारत-पाकिस्तान धार्मिक यात्राओं के नियम बदल दिए हैं। यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आए पाक जासूसी नेटवर्क और हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा केस के बाद लिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहां के प्राइवेट टूर ऑपरेटर धार्मिक यात्रा के नाम पर भारतीय नागरिकों को स्पॉन्सर करते हैं, ताकि उनसे जासूसी करा सकें। इसे देखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान से चलने वाले सभी प्रकार के प्राइवेट स्पॉन्सर्ड टूर पर पाबंदी लगा दी है। वीजा की शर्तें भी बदल दी गई हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के टूरिज्म इंचार्ज हरकीरत सिंह ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ज्योति मल्होत्रा जैसे जासूसी केस मिलने के बाद से प्राइवेट स्पॉन्सर टूर बंद कर दिए गए हैं। पहले पाकिस्तान जाने वाले लोग वहां की एजेंसी से संपर्क कर टूर प्रोग्राम अरेंज करते थे।

कांग्रेस क्या चाहती है, कश्मीरी जेल जाएं

उमर ने पूछा, कहा-सरकारी कार्यक्रमों में नियम मानना जरूरी

कश्मीर में पूरा वंदे मातरम गाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वंदे मातरम के सभी छह पैरा को लेकर जो प्रावधान लागू है, उसका सरकार को पालन करना होगा। वंदे मातरम के दौरान खड़े न होने के कानूनी परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने पूछा, कांग्रेस क्या चाहती है, कि कश्मीरियों को इस कारण जेल में डाल दिया जाए। उमर ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में लागू नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। ये नियम सिर्फ जम्मू-कश्मीर नहीं, बल्कि पूरे देश में सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होते हैं। दरअसल, सोमवार को श्रीनगर में सीएम उमर और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला की मौजूदगी में राष्ट्रीय गीत का पूरा संस्करण हुआ था। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते अपील की थी कि वह कांग्रेस के साथ खड़ी रहे।

पार्टी के फैसले और कानूनी जिम्मेदारी दोनों अलग

हालांकि, उमर ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी वंदे मातरम को पार्टी के तौर पर नहीं अपनाया है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगी। यह पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक फैसले का विषय है। उमर ने कहा कि पार्टी के फैसले और सरकार की कानूनी जिम्मेदारी को अलग-अलग समझना चाहिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल के समापन समारोह में भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों प्रस्तुत किए जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

साहिबगंज में गंगा नदी ने चार साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जलस्तर 28.72 मीटर तक पहुंचा, लोग परेशान

साहिबगंज, एजेंसी। झारखंड का साहिबगंज जिला बाढ़ से प्रभावित है. शुक्रवार सुबह गंगा नदी का जलस्तर 28.72 मीटर तक पहुंच गया, जो पिछले चार सालों में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा स्तर है. इससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

बता दें कि पिछले साल गंगा का अधिकतम जलस्तर 28.70 मीटर तक पहुंचा था. इससे पहले के सालों में अधिकतम स्तर 28.06 मीटर (2024), 27.38 मीटर (2023) और 28.60 मीटर (2022) रहा था. अभी जलस्तर धीमी गति से बढ़ रहा है.

केंद्रीय जल आयोग के साइट इंचार्ज छोटे लाल मालतो ने बताया कि बक्सर और मुंगेर के बीच नदी का जलस्तर घट रहा है और बाकी जगहों पर स्थिर है. हालांकि, कोसी नदी से पानी छोड़े जाने के कारण साहिबगंज में गंगा का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही जलस्तर स्थिर हो जाएगा.

गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए, नदी के किनारे स्थित सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 11 और 12 सितंबर तक दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. नतीजतन, बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल अब सोमवार को खुलेंगे.

गंगा के बढ़ते जलस्तर और जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों को लगातार मजबूत कर रहा है. प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बाढ़ प्रभावित परिवारों तक जरूरी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए जमीन पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. इन प्रयासों के तहत, आज गोपालपुर, घिसु टोला, मकईया टोला और बांसकोला जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया. इस निरीक्षण का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन आईन्द और साहिबगंज अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टुडू ने ह्छ्क्र्र्ल की टीम और कर्मचारियों के साथ मिलकर किया.

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया और उनके बीच खाद्य सामग्री बांटी. इस मौके पर, अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वे बाढ़ से प्रभावित लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें, राहत और खाने-पीने की चीजें पहुंचाने में कोई कमी न होने दें, प्रभावित परिवारों तक समय पर मदद पहुंचाएं और इलाके पर लगातार नजर रखें.

उपायुक्त के निर्देशानुसार जनता दरबार का हुआ आयोजन

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता /

धनबाद।उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार आज समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जन शिकायत कोषांग के प्रभारी उमेश हांसदा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं।जनता दरबार में भूमि विवाद, नाली निर्माण, लंबित वेतन, जमीन की मापी, अवैध कब्जा, सड़क निर्माण, दिव्यांग पेंशन, विभिन्न प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड समेत कई अन्य मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं।जन शिकायत कोषांग के प्रभारी उमेश हांसदा ने लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर करमा पर्व 2026 की तैयारियों को लेकर प्रमुख सरना समितियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) रांची धनंजय एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची कुमार रजत द्वारा संयुक्त रूप से बैठक की

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची।जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) रांची धनंजय एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची कुमार रजत द्वारा संयुक्त रूप से आगामी करमा पर्व 2026 को लेकर सभी प्रमुख सरना समितियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

यह बैठक समाहरणालय ब्लॉक-ए में स्थित अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा, केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप, जगलाल हेम्ब्रम, सुश्री ज्योत्सना करकेट्टा, केंद्रीय घुमक्कड़िया करम टोली चौक छोटा नागपुर सरना समिति नामकुम रांची के सचिव तथा जिले की अन्य प्रमुख सरना समितियों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सरना समितियों के प्रतिनिधियों ने करमा पर्व को सुव्यवस्थित एवं भव्य ढंग से आयोजित करने के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। उन्होंने करमा पूजा स्थलों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने, बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने, अखड़ा में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा करमा पर्व के अवसर पर शराब बंदी लागू करने की मांग की। साथ ही, करमा करने वाले श्रद्धालुओं को साड़ी एवं धोती उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया। अधिकारियों ने सभी प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना और पर्व की तैयारियों को लेकर सहयोग एवं समन्वय का आश्वासन दिया। बैठक में करमा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाएंगे : शिल्पी नेहा तिर्की

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ना जरूरी है। सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं पर बजट खर्च करना नहीं, बल्कि ऐसी योजनाओं को जमीन पर उतारना है, जिनका सीधा और स्थायी लाभ किसानों, उत्पादकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिले। मंत्री शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित सभागार में सहकारिता प्रभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में विभाग के सचिव, विशेष सचिव, निबंधक, सहयोग समितियां तथा विभिन्न एपेक्स सोसाइटी के प्रबंध निदेशक मौजूद रहे। बैठक में बजटीय प्रावधान, व्यय की प्रगति, संचालित योजनाओं और चालू वित्तीय वर्ष में शुरू नई योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज-कम-मार्केटिंग सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए डीपीआर तैयार कराने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक प्राप्त डीपीआर अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को देश में बेहतर लॉजिस्टिक और कोल्ड-चेन व्यवस्था विकसित करने वाली अग्रणी कंपनियों को कंसल्टेंसी के लिए आमंत्रित करने और उनके तकनीकी सुझाव लेने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 20 जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। नई परियोजना में आधुनिक तकनीक, ऊर्जा दक्षता, बेहतर लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग व्यवस्था और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बैठक में सिद्धकोफेड की ओर से प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए मड़ुवा के आटे की आपूर्ति के प्रस्ताव की भी समीक्षा की गई। पायलट प्रोजेक्ट में रांची, खूंटी और सरायकेला-खरसावां को शामिल किया गया है।

पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी, 8 वर्षों की शादी पर भारी पड़ा सोशल मीडिया का प्यार

साहिबगंज, एजेंसी। जिले के मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक अनोखा प्रेम विवाह चर्चा का विषय बन गया. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ 8 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करते हुए उसका विवाह उसके प्रेमी से करा दिया. इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरे मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी.

थाना क्षेत्र के विनोद मंडल की शादी करीब आठ साल पहले हुई थी. विनोद मंडल ने बताया कि पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के बाखरपुर गांव के एक युवक गोलू कुमार से हुआ. इस बीच धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया.

विनोद के अनुसार, उसने कई बार अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे. इधर, लड़की के घरवाले भी प्रेमी से शादी कराने के लिए राजी हो गए. विनोद मंडल ने दोनों की इच्छा को देखते हुए पत्नी का विवाह उसके प्रेमी गोलू कुमार से कराने का निर्णय लिया. जिसके बाद गुरुवार को दोनों का विवाह संपन्न कराया गया. विवाह के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. वहीं नवविवाहित प्रेमी जोड़े ने बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा और आपसी सहमति से शादी की है. दोनों ने आगे बताया कि वे आगे साथ रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं. गोलू कुमार ने बताया कि उसके माता-पिता भी इस शादी के लिए राजी हैं और वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखेगा.

झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: दोबारा होगी जेईटी परीक्षा, 2 माह के भीतर जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

रांची, एजेंसी। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य के उच्च शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र को लेकर दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेईटी को छह माह में दोबारा कराने और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी में अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों पर दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का कड़ा निर्देश दिया है.?

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के नियमित पदों पर सीधी नियुक्ति के बजाय संविदा के आधार पर ली जा रही सेवाओं के खिलाफ अनिकेत ओहदार व अन्य द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह जेपीएससी को जेट परीक्षा आयोजित करने के लिए नए सिरे से अधियाचना भेजे.

अधियाचना मिलने के 6 महीने के भीतर आयोग को परीक्षा आयोजित कर उसका अंतिम परिणाम घोषित करना होगा.? सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि राज्य सरकार पूर्व में छ्ब्श्रञ्ज परीक्षा रद्द कर चुकी है. चूंकि विज्ञापन रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए अदालत ने सरकार को नई सिरे से प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. जेपीएससी ने अदालत को बताया कि वर्ष 2024 में जेट परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी जा रही थीं, लेकिन इसी दौरान आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे और तकनीकी अड़चनों के कारण प्रक्रिया रुक गई और अंततः राज्य सरकार ने विज्ञापन रद्द कर दिया. हाई कोर्ट ने दूसरा बड़ा फैसला जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सुनाया है. राज्य के वन विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी को लेकर अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेपीएससी के शीर्ष पदों पर खाली पड़ी जगह पर गहरी चिंता व्यक्त की.

झारखंड में निवास कर रहे अन्य राज्यों में जन्में मतदाता आयु एवं जन्म स्थान के सत्यापन हेतु अपने संबंधित राज्य से जारी मान्य दस्तावेज कर सकते हैं प्रस्तुत– के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने के लिए उसका भारत का नागरिक होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना तथा संबंधित अर्हता तिथि (वर्तमान एसआईआर के लिए 1 अक्टूबर 2026) को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। झारखण्ड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के क्रम में मतदाताओं की पात्रता का सत्यापन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड की मतदाता सूची में ऐसे मतदाता भी पंजीकृत हैं, जिनका जन्म अथवा पूर्व निवास किसी अन्य राज्य में रहा है। दावा-आपत्ति एवं सुनवाई की प्रक्रिया के क्रम में यदि ऐसे मतदाताओं को आयु, जन्म अथवा अन्य विवरणों के सत्यापन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस प्राप्त हुआ है, तो वे इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्ढ्क्रके लिए मान्य दस्तावेज, अपने संबंधित राज्य के द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित दस्तावेज का झारखण्ड से ही निर्गत होना आवश्यक नहीं है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता अपने जन्म स्थान, आयु अथवा पारिवारिक संबंध के सत्यापन के लिए वंशावली अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची, खतियान, शैक्षणिक दस्तावेज सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के लिए निर्धारित अन्य मान्य दस्तावेज अपने संबंधित राज्य से प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों का परीक्षण संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि नोटिस प्राप्त होने पर निर्धारित समय पर सुनवाई में उपस्थित होकर उपलब्ध मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए पात्रता के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्णय सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र अथवा विदेशी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

क्लब फुट से पीड़ित 3 बच्चों का हुआ सफल ऑपरेशन

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद।उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के सौजन्य से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान जारी है। इस क्रम में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एसएनएमएमसीएच) में क्लब फुट से पीड़ित 3 बच्चों का आज सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि आरबीएसके के माध्यम से चिन्हित बच्चों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराते हुए आवश्यक जांच, उपचार एवं सर्जरी की सुविधा प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि एसएनएमएमसीएच में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में तीनों बच्चों की क्लब फुट संबंधी समस्या का सफल ऑपरेशन किया गया।

उन्होंने कहा कि आरबीएसके का उद्देश्य बच्चों में जन्मजात एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान कर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित करना है। जिले में चिन्हित बच्चों को आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श, उपचार एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे स्वस्थ एवं सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ सकें।

गिरने की कगार पर लातेहार की पुलिया! कई गांवों का मुख्यालय से कट सकता है संपर्क

लातेहार, एजेंसी। जिला मुख्यालय को लगभग आधा दर्जन गांव से जोड़ने वाली गुरगु–ओरवाई पथ की पुलिया काफी जर्जर और खतरनाक हो गई है. लातेहार सदर प्रखंड के दो पंचायत को आपस में जोड़ने वाली यह पुलिया लगभग आधा दर्जन गांवों को प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ती है. दरअसल, लातेहार जिले में इस साल लगातार मूसलाधार बारिश हुई. बताया जाता है कि भारी बारिश के कारण लातेहार सदर प्रखंड के गुरगु गांव में स्थित एक बांध टूट जाने के कारण नदी की धार इतनी तेज हो गई थी कि पुलिया के नीचे बना फाउंडेशन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिया का मुख्य खंभा भी नीचे से मिट्टी कटने के कारण काफी कमजोर हो गया. अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पुलिया पर आवागमन भी खतरनाक होता जा रहा है. ग्रामीण बताते हैं कि यदि अगली बार कभी जोरदार बारिश हुई और नदी में बाढ़ आई तो संभावना है कि पुलिया चलने लायक भी न बचे. ग्रामीणों ने बताया कि यह पुलिया इस इलाके के लिए काफी महत्वपूर्ण है. दो पंचायत तरवाडीह और बेंदी को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण पुलिया लगभग आधा दर्जन गांवों को जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती है. लातेहार सदर प्रखंड के ओरवाई, छतरीटांड़, भोकाखाड़ आदि गांव के सैकड़ों लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है.

माइनिंग चालान के कारण संवेदकों का भुगतान अटका, सरकार से तत्काल राहत की मांग

माइनिंग चालान के फेर में अटके करोड़ों के बिल, संवेदकों ने सरकार से तत्काल राहत मांगी

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता , रांची /

रांची: झारखंड में माइनिंग चालान की समस्या और बिटुमिन के बढ़े हुए दाम को लेकर रांची सेंटर बिल्डर्स एसोसिएशन सहित संवेदक संगठनों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक प्रधान ने कहा कि माइनिंग चालान की व्यवस्था में बदलाव के कारण पिछले चार महीने से बड़ी संख्या में संवेदकों का भुगतान अटका हुआ है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और संवेदकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शुक्रवार को स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक प्रधान ने कहा कि संवेदकों की तीन प्रमुख समस्याएं सरकार के समक्ष रखी गई थीं। इनमें बिटुमिन की कीमत में वृद्धि की प्रतिपूर्ति, झारखंड के शेड्यूल ऑफ रेट (एसओआर) को वर्तमान बाजार दर के अनुरूप संशोधित करना और माइनिंग चालान की समस्या प्रमुख है।उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 अगस्त 2026 को एसओआर को संशोधित कर बड़ी राहत दी है। पहले चार वर्ष पुराने दर पर निविदाएं निकल रही थीं, जबकि अब नए विकास कार्यों में वर्तमान बाजार दर के अनुरूप दर लागू होगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के अभियंता प्रमुखों के प्रति आभार जताया।माइनिंग चालान ने बढ़ाई परेशानीअशोक प्रधान ने कहा कि 27 अप्रैल 2026 को खान विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद डबल रॉयल्टी भुगतान की व्यवस्था बंद कर दी गई। इसके बाद संवेदकों को मिट्टी और बालू के चालान की उपलब्धता में परेशानी हो रही है। पर्याप्त चालान नहीं मिलने के कारण काम पूरा करने के बावजूद संवेदकों के बिलों का भुगतान अटक गया है।उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसी संवेदक का पांच करोड़ रुपये का बिल है, लेकिन यदि उसमें महज 50 हजार रुपये के मिट्टी के चालान की कमी है तो पूरा पांच करोड़ रुपये का भुगतान रुक जा रहा है। पिछले चार महीने से भुगतान नहीं होने के कारण संवेदकों पर बैंक की ईएमआई और अन्य वित्तीय दायित्वों का दबाव बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे कोलेकर संवेदकों का प्रतिनिधिमंडल खान विभाग, मुख्य सचिव और पथ निर्माण विभाग के सचिव से मिल चुका है। अधिकारियों ने व्यवस्था बनने तक अस्थायी राहत देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में ठोस निर्णय नहीं हो सका है।

बिटुमिन के बढ़े दाम की प्रतिपूर्ति की मांग–एसोसिएशन ने पुराने चल रहे ठेकों में बिटुमिन की बढ़ी कीमत की प्रतिपूर्ति की भी मांग की। अशोक प्रधान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बिटुमिन की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। नई दरों में तो संशोधन संभव है, लेकिन पुराने और चल रहे अनुबंधों में संवेदकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग की कुछ बड़ी योजनाओं में बढ़ी लागत की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है, लेकिन छोटी योजनाओं और ग्रामीण विकास एवं नगर विकास विभाग की कई योजनाओं में संवेदकों को राहत नहीं मिल रही है।

मुद्रास्फीति की दरों में लगातार वृद्धि ने बढ़ाई चिंता, उपभोक्ता सामान के दामों की बढ़ोतरी जनता परेशान!

रांची, एजेंसी। महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। सामान्य उपभोक्ता वस्तु से लेकर लग्जरी सामानों के दामों में जारी मूल्य वृद्धि थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीनी, प्याज, सरसों तेल, घी, रिफाइन, चावल, आटा जैसी जरूरत के सामानों में हो रही तेजी ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रखा है।

वैश्विक एवं अन्य कारणों की वजह से झारखंड सहित देशभर में उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि का यह ट्रेंड इस साल के शुरुआती महीनों से जो जारी हुआ, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हर महीने बढ़ता जा रहा है।

भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 107।94 पहुंच गया जो जून महीने की तुलना में ।94 अधिक है। बात यदि मुद्रास्फीति की करें तो देश में जुलाई 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4।45 प्रतिशत दर्ज की गई है जबकि 2025 के जुलाई में 1।61% मुद्रास्फीति देश में थी। इस साल जनवरी में मुद्रास्फीति 2।74%, फरवरी में 3।21%, मार्च में 3।4%, अप्रैल में 3।48%, मई में 3।93%, जून में 4।38% और जुलाई में 4।45% पर पहुंच गया है। बता दें कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादन और उत्पादन पर नज़र रखने वाले प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक सूचकांक जारी करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वह पैमाना है जो समय के साथ उपभोक्ताओं द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में आए बदलाव को मापता है यानी यह एक महंगाई का मीटर है। जिसका निर्धारण भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है। इसका मुख्य उपयोग अर्थव्यवस्था में खुदरा महंगाई का पता लगाने के लिए किया जाता है।

चतरा विधायक के बेटे से मारपीट मामले में नया मोड़, सौरभ समेत पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज

रांची, एजेंसी। राजधानी रांची के एमिटी यूनिवर्सिटी गेट पर हुई मारपीट और अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में दूसरे पक्ष के द्वारा भी विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है. पहले एफआईआर जनार्दन पासवान के बेटे के द्वारा करवाई गई थी. अब जनार्दन पासवान के बेटे और उसके साथियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.

यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 20 वर्षीय छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट, गाली-गलौज, गला दबाने, सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में विधानसभा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. एफआईआर में सौरभ कुमार (जनार्दन पासवान के बेटे), वासु दुबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक शिवा और तीन-चार अन्य युवाओं को आरोपी बनाया गया है.

स्न्ह्रक्र के अनुसार, शिकायतकर्ता का बेटा लकी राज एमिटी यूनिवर्सिटी में बीबीए सेकंड ईयर का छात्र है. शिकायत में कहा गया कि 7 सितंबर को लकी राज सुबह करीब 9.30 बजे घर से कॉलेज के लिए निकला था. दोपहर करीब दो बजे क्लास खत्म होने के बाद जब वह कॉलेज से बाहर निकल रहा था. इस दौरान मेन गेट के सामने सौरभ कुमार, वासु दूबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक सिंह और तीन-चार अन्य युवक खड़े थे.

शिकायतकर्ता प्रियंका सिंह का आरोप है कि उस व्यक्ति के पास बीयर और शराब की बोतलें और बेल्ट थी और वह उस समय शराब और सिगरेट भी पी रहा था. आरोप है कि छात्र को देखते ही वासु दुबे ने उसे जबरदस्ती रोका और गाली-गलौज करने लगा. छात्र ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वे परिचित हैं, फिर गाली क्यों दे रहे हैं. इसके बाद, सौरभ कुमार ने छात्र का कॉलर पकड़ा और उसके साथ मारपीट करने लगा.

स्न्ह्रक्रमें आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान छात्र के गले से सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये छीन लिए गए. शिकायत के अनुसार, सौरभ ने कथित तौर पर यह भी कहा कि उसके पिता विधायक हैं और उसकी हत्या कर देने पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा. साथ ही छात्र को एससी/एसटी एक्ट में फंसाकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया. ये सभी बातें शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं.

शिकायत में आगे कहा गया कि सौरभ कुमार ने जान मारने की नीयत से छात्र का गला दबाने की कोशिश की. जबकि वासु दूबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक सिंह और अन्य युवकों ने लात-घूंसे और बेल्ट से पीटा. हंगामा देखकर कॉलेज के दूसरे छात्र भी वहां पहुंच गए थे. शिकायत के मुताबिक, भीड़ बढ़ने पर सौरभ कुमार ने अपने साथियों को बुलाने की कोशिश की और कथित तौर पर पिस्टल लाकर गोली मारने की बात कही. इसके बाद कॉलेज के अन्य छात्रों ने किसी तरह लकी राज को आरोपियों से बचाया.

एफआईआर में कहा गया कि मौके पर मौजूद छात्रों ने पुलिस की मदद के लिए 112 पर फोन करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल नहीं लगी. भीड़ बढ़ने पर सौरभ को छोड़कर उसके बाकी साथी वहां से चले गए. इसके बाद सौरभ के कथित तौर पर नशे में होने और लगातार गाली-गलौज करने के कारण लकी राज और कॉलेज के कुछ अन्य छात्रों ने उसे गाड़ी में बैठाकर विधानसभा थाना ले जाने का फैसला किया. शिकायत के मुताबिक, रास्ते में सौरभ ने किसी को फोन कर अपने अपहरण की झूठी सूचना देने की कोशिश की और अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में डाल दिया. बाद में उसे गाड़ी से उतार दिया गया और लकी राज पैदल उसे लेकर विधानसभा थाना पहुंचा.

छात्र की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब से उनका बेटा एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, तब से सौरभ कुमार और उसके अन्य साथी कॉलेज के अंदर और बाहर उसे परेशान करते थे. उनका बेटा घर आकर इन घटनाओं की जानकारी देता था और इसी वजह से उसने कॉलेज नहीं जाने की बात भी कही थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 304(2), 351(2), 351(3), 352 और 3(5) के तहत विधानसभा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है.

संक्षिप्त समाचार

साहिबगंज में बाबूलाल मरांडी का आरोप, सरकार को बाढ़ पीड़ितों की चिंता नहीं

साहिबगंज, एजेंसी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की परवाह नहीं कर रही है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहत सामग्री के नाम पर सरकारी राशि की बंदरबांट हो रही है. बाढ़ पीड़ितों को मात्र दो-दो किलो चूड़ा और गुड़ दिया जा रहा है. इससे पीड़ितों की क्या हालत होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है.

बुधवार को साहिबगंज पहुंचने पर कई लोगों ने राहत सामग्री वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की. इसके बाद मरांडी ने उपायुक्त को फोन कर जानकारी ली और मिलने के लिए बुलाया. लेकिन उपायुक्त ने मिलने से इनकार कर दिया.

नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि जब उपायुक्त को नेता प्रतिपक्ष से मिलने का समय नहीं है, तो आम जनता के साथ वे क्या व्यवहार करते होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं. उन्होंने कहा कि उपायुक्त जनता के सेवक होते हैं, नवाब नहीं.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार छात्रों का आंदोलन चल रहा है इस लिए वे इस मामले को तूल नहीं देना चाहते. लेकिन अगली बार वे स्टेडियम में धरना पर बैठेंगे और उपायुक्त को वहां आकर मिलना ही होगा.

बता दें कि राज्य में जेपीएससी और जेएससी जैसी परीक्षाओं में धांधली तथा छात्रों पर केस के विरोध में भाजपा के आक्रोशपूर्ण आंदोलन में शामिल होने के लिए बाबूलाल मरांडी साहिबगंज आए हुए थे. शहर के पूर्वी फाटक से आंदोलन शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट भवन तक पहुंचा. आंदोलन की खबर मिलते ही फाटक बंद कर दिया गया. उपायुक्त की अनुपस्थिति में एक शिष्टमंडल ने एडीसी को आवेदन सौंपा.

पलामू में धान खरीद में लाखों का घोटाला, कंप्यूटर ऑपरेटर निकला मास्टरमाइंड, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पलामू, एजेंसी। जिले के नावाबाजार स्थित कंडा पैक्स में धान घोटाला का मामला सामने आया है. धान खरीद को लेकर फर्जी आईडी बनाकर करीब 13.86 लाख रुपये का घोटाला किया गया है. इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड कंडा पैक्स का कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल गुप्ता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं राहुल गुप्ता का दोस्त फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

दरअसल, नावाबाजार के कंडा पैक्स में करीब छह हजार क्विंटल धान की खरीद हुई थी. पहले चरण में सरकार ने करीब चार हजार क्विंटल धान की राशि का भुगतान कर दिया था, जबकि करीब दो हजार क्विंटल धान की राशि का भुगतान बाकी था. धान बेचने वाले किसान पैक्स पर भुगतान का दबाव बना रहे थे. इसी दौरान पैक्स में धान खरीद का हिसाब-किताब शुरू किया गया.

हिसाब-किताब के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए. पता चला कि फर्जी आईडी बनाकर फर्जी तरीके से 500 क्विंटल धान खरीदा गया दिखाया गया, जो गोदाम तक पहुंचा ही नहीं. पूरे मामले में पैक्स के अध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह ने नावाबाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई.

नावाबाजार थाना पुलिस ने अनुसंधान के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. जांच में करीब 13.86 लाख रुपये का धान घोटाला सामने आया. राहुल गुप्ता ने फर्जी तरीके से किसानों की आईडी बनाई और उनमें भुगतान करवाया. उसने अपनी पत्नी और मां की भी फर्जी आईडी बनाई तथा उनके बैंक खातों में पैसे भेजे.

जेएसएससी-सीजीएल नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

रांची, एजेंसी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के अमल पर रोक लगा दी. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. इन मामलों में शालिनी सुंडी व अन्य, रोजलिन श्वेता तिग्गा एवं अन्य तथा ऋषिकेश सज्जन एवं अन्य याचिकाकर्ता हैं.

हालांकि, सभी याचिकाकर्ताओं को अंडरटेकिंग दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट का अंतिम आदेश उन पर बाध्यकारी होगा और उसके आधार पर सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी.

धनबाद में 'लुटेरी दुल्हन' गैंग का खुलासा! शादी के नाम पर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

धनबाद, एजेंसी। लुटेरी दुल्हन का एक मामला झारखंड के धनबाद जिला में सामने आया है। जहां शादी के नाम पर ठगी और लूट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

जिला के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो दूसरे राज्यों के शादी के इच्छुक परिवारों को अपने जाल में फंसाकर धनबाद बुलाता था। आरोप है कि राजस्थान के एक परिवार को शादी का झांसा देकर यहां बुलाया गया।

पहले उनसे शादी के लिए खरीदारी कराई गई और फिर एक गांव में ले जाकर युवती की मांग में सिंदूर डलवाया गया। इसके बाद परिवार को कथित तौर पर सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की गई और मोबाइल व जेवरात छीन लिए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मामला 7 सितंबर की देर शाम का बताया जा रहा है। राजस्थान निवासी रमेश नट ने बरवाअड्डा थाना में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, 3 सितंबर को सपना नाम की महिला ने फोन के जरिए रमेश नट से संपर्क किया था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसके भतीजे की शादी के लिए लड़की उपलब्ध है। इसके बाद व्हाट्सऐप पर दो युवतियों की तस्वीरें भी भेजी गईं।

लड़की पसंद आने के बाद शादी की बातचीत आगे बढ़ी और रमेश नट अपने भाई, भतीजे इकबाल और भाभी के साथ राजस्थान से धनबाद पहुंचे। आरोप है कि धनबाद पहुंचने के बाद सपना और उसके साथियों ने उन्हें अपने साथ लिया और शादी के नाम पर खरीदारी कराई गई।

परिवार से कपड़े, गहने और शादी से जुड़ा अन्य सामान खरीदवाया गया। इसके बाद उन्हें एक गांव में ले जाया गया, जहां युवती की मांग में सिंदूर भरवाकर शादी की रस्म पूरी होने की बात कही गई।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के बाद लड़के वालों को घर चलकर भोजन करने के लिए कहा गया। जब परिवार ने वहां जाने से इनकार किया तो कथित तौर पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें वहां से भगा दिया।

पीड़ित परिवार की शिकायत मिलने के बाद बरवाअड्डा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके अलावा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, कॉल डंप और लोकेशन समेत तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।

जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से शादी के लिए खरीदे गए कपड़े, गहने और अन्य सामान भी बरामद किया।

पलामू के मेदिनीनगर में घरेलू सहायिका का कारनामा, लाखों के जेवरात गायब, पूरे परिवार को पुलिस ने भेजा जेल

पलामू, एजेंसी। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहाड़ी मोहल्ला में एक घर में काम करने वाली नौकरानी और उसकी बेटी ने मिलकर लाखों रुपये के सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के कारण चोरों की यह साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौकरानी, उसकी बेटी और दो बेटों समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं, जिसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह पूरा मामला पहाड़ी मोहल्ला के रहने वाले नेशात अहमद के घर का है। उनके घर से अचानक सोने के जेवरात गायब हो गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने तुरंत मेदिनीनगर टाउन थाने में दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस की टीम ने घर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कई अन्य अहम बिंदुओं पर अपनी जांच आगे बढ़ाई। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के बाद पुलिस के शक की सुई घर में काम करने वाली मेड (घरेलू सहायिका) पर जाकर टिक गई। सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चोरी की इस घटना को घर में मेड का काम करने वाली सगुफता परवीन और उसकी बेटी मुस्कान परवीन ने मिलकर अंजाम दिया था। जेवरात चुराने के बाद उन्होंने इसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी अपने दो बेटों को सौंप दी। सगुफता के बेटे समीर आलम और सोनू आलम जब इन चोरी के जेवरात को बाजार में बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने सगुफता, मुस्कान, समीर और सोनू को गिरफ्तार कर लिया।

झारखंड एंबुलेंस कर्मचारी संघ की बैठक, 108 एंबुलेंस सेवा संचालन एवं कर्मचारियों की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा

रांची, एजेंसी। 108 एंबुलेंस सेवा कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश एवं सभी जिलों के पदाधिकारियों ने रांची में बैठक कर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। बुधवार को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, धुर्वा, रांची में आयोजित बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने की।

संघ ने कहा कि स्ब्ह, ह्यरू कार्यालय द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जनों को जिला स्तर पर 108 एंबुलेंस सेवा के संचालन एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, बावजूद इसके कई जिलों में जिला स्तर से एंबुलेंस सेवा का संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है।

एंबुलेंस संघ द्वारा पूर्व में सरकार को वर्तमान 108 एंबुलेंस सेवा की टेंडर प्रक्रिया पूर्णतः निरस्त करने, जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से सेवा संचालन शुरू करने, कंपनी द्वारा सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल करने तथा कर्मचारियों को वैधानिक श्रमिक अधिकार की सुविधा उपलब्ध करने की मांग की गई थी, साथ ही, 08 सितंबर 2026 तक जिला स्तर पर एंबुलेंस संचालन शुरू करने का आग्रह किया गया था। निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर संघ ने बुद्धवार चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया।

झारखंड एंबुलेंस संघ ने स्पष्ट कहा कि कर्मचारी कभी भी 108 जैसी महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवा को बाधित कर हड़ताल नहीं करना नहीं चाहता, संघ द्वारा सरकार एवं संबंधित अधिकारियों से कई बार मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया गया तथा समाधान का आश्वासन भी मिला, लेकिन आश्वासनों को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। इसी कारण संघ अब आंदोलन का निर्णय लेने के लिए बाध्य हुआ है।

बैठक में मुख्य रूप से रमाशंकर प्रसाद, प्रभारी एंबुलेंस कर्मचारी संघ एवं प्रदेश मंत्री, भारतीय मजदूर संघ उपस्थित रहे। इसके अलावा मुकेश कुमार, अजय कुमार दांगी, रविकांत देव, मृत्युंजय कुमार, कुणाल बनर्जी, सुखलाल उरांव, मदन कुमार, आशीष कुमार, चंदन कुमार, ललन चौधरी, राजू ठाकुर, राजेश कुमार, श्री राम कुमार, नेहाल कुमार, ओम विजय, निशा प्रभा, आनंद कुमार, निर्भय राणा, सुरेंद्र लहरी, रविंद्र शर्मा, सुखबीर उरांव, पंकज कुमार, मनोज साहू, कृष्ण कुमार यादव, सुबोध कुमार यादव जिला मंत्री, रांची जिला, भारतीय मजदूर संघ सहित सभी जिलों के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की कि आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व जिला स्तर पर 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन तत्काल प्रारंभ किया जाए, टेंडर प्रक्रिया निरस्त की जाए तथा हटाए गए कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल किया जाए।

बैंक अधिकारी बनकर शेयर बाजार में निवेश का झांसा, यूपीआई से 9.20 लाख की ठगी

रांची, एजेंसी। राज्यभर में साइबर ठगी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहे हैं, इसके बावजूद लोग झांसे में आ जा रहे हैं. केवल रांची में साल 2026 में अब तक 200 से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं. ताजा मामला रांची के कांके क्षेत्र में रहने वाले मंगरा उरांव का है. मंगरा से एक साइबर अपराधी बैंक अफसर बनकर मिला और शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 9 लाख की ठगी कर ली.

कांके थाना क्षेत्र के पतगाई निवासी मंगरा उरांव ने साइबर अपराध थाना, रांची में 9 लाख 20 हजार 2 रुपये की यूपीआई के माध्यम से ठगी किए जाने की शिकायत की है. शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) और 66(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

एफआईआर में मंगरा उरांव ने बताया कि संतोष कुमार मलिक से उसकी पहचान बैंक के माध्यम से हुई थी. आरोप है कि संतोष खुद को बैंक का अधिकारी बताता था. उसने मंगरा को भरोसा दिलाया कि बैंक में पैसा रखने की तुलना में शेयर बाजार और ग्रो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से अधिक कमाई होगी. मंगरा उसके झांसे में आ गया. इसके बाद आरोपी ने उससे बैंक संबंधी दस्तावेज और मोबाइल फोन ले लिया.

शिकायत के अनुसार, संतोष ने मंगरा का मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक मांगी और 15 मार्च 2026 को उसके मोबाइल में फोन-पे बना दिया.

खतरे की आहट के बावजूद नहीं बदली तस्वीर, भू-धंसान की दहशत में घर छोड़ने को मजबूर 40 परिवार!

धनबाद, एजेंसी। जिला में जोगता थाना क्षेत्र के तिनपटिया में मंगलवार की सुबह जमीन धंसने की घटना ने सिर्फ एक परिवार से उसका मासूम नहीं छीना, बल्कि परिवारों को उनके घरों से भी दूर कर दिया।

सुबह करीब पांच बजे अचानक तेज आवाज के साथ जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, देखते ही देखते कई घर इसकी चपेट में आ गए। कुछ लोग मलबे में फंस गए तो घरों में रखा सामान जमीन के अंदर समा गया। स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बचाव अभियान चलाया और फंसे लोगों को बाहर निकाला। चार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया लेकिन करीब चार साल के एक बच्चे की मौत हो गई।

इस हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जमीन क्यों धंसी, बल्कि यह भी है कि क्या इस खतरे की आहट पहले ही मिल चुकी थी? ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें लंबे समय से इलाके की जमीन को लेकर आशंका थी। उनका कहना है कि संभावित खतरे की जानकारी बीसीसीएल प्रबंधन को कई बार दी गई थी और इलाके को सुरक्षित करने की मांग की गई थी। ग्रामीणों के आरोप के मुताबिक, उनकी शिकायतों पर अपेक्षित गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई।

दूसरी ओर बीसीसीएल इस दावे से अलग तस्वीर पेश कर रहा है। सिजुआ एरिया के महाप्रबंधक निरझर

चक्रवर्ती का कहना है कि पूर्व में इलाके में बालू भराई के जरिए जमीन को सुरक्षित करने की पहल की जा रही थी लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और बालू भराई का काम नहीं होने दिया। यानी तिनपटिया की घटना के बाद एक तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि खतरे के बावजूद प्रबंधन ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। जबकि दूसरी ओर प्रबंधन का दावा है कि सुरक्षा के लिए पहल की गई थी लेकिन लोगों के विरोध के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। अब इन दोनों दावों के बीच सच क्या है, यह जांच का विषय है। तिनपटिया में रहने वाले लोगों का कहना है कि मंगलवार की घटना उनके लिए अचानक जरूर थी लेकिन इलाके की जमीन को लेकर आशंका बिल्कुल नई नहीं थी। ग्रामीणों का दावा है कि जमीन की स्थिति और संभावित भू-धंसान को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, उन्होंने प्रबंधन से कहा था कि इलाके को सुरक्षित किया जाए और यदि जमीन के नीचे किसी पुरानी खदान या खनन गतिविधि का असर है तो उसकी तकनीकी जांच कराई जाए। लोगों का कहना है कि उन्हें डर था कि जमीन कभी भी धंस सकती है।ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपनी चिंता अधिकारियों तक पहुंचाई, लेकिन कोई ऐसा स्थायी इंतजाम नहीं किया गया जिससे लोगों को भरोसा हो सके कि वे सुरक्षित हैं। इस हादसे के बाद ग्रामीण इसी बात को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पहले ही इलाके का सर्वे कराया जाता, खतरे वाले हिस्से की पहचान होती और परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता, तो शायद मंगलवार की घटना में एक मासूम की जान नहीं जाती। हालांकि, ग्रामीणों के इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह जांच का विषय है कि शिकायतें कब दी गईं, किस अधिकारी को दी गईं, उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं और शिकायतों के बाद प्रबंधन ने क्या कार्रवाई की। मंगलवार की सुबह जब जमीन धंसी, उस वक्त बस्ती में पानी की सप्लाई शुरू हुई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई लोग पानी भरने के लिए घरों से बाहर निकल चुके थे। इसी दौरान अचानक धड़ाम-धड़ाम की आवाज सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। कुछ ही पलों में कई घरों के आसपास जमीन नीचे चली गई। स्थानीय निवासी शिव राखन सिंह बताते हैं कि जिस कमरे में उनका बेटा सोता था, वहां रखी चौकी तक जमीन में समा गई। लेकिन गनीमत रही कि उनका बेटा पानी भरने के लिए कुछ देर पहले ही कमरे से बाहर निकल गया था। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर होते, तो हादसे का असर और भयावह हो सकता था। सुबह का समय होने के कारण कुछ लोग बाहर थे और आसपास के लोगों ने भी आवाज सुनकर तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ लगा दी। यही वजह रही कि राहत और बचाव का काम स्थानीय स्तर पर तत्काल शुरू हो गया।

इस हादसे के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण काम था मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना। स्थानीय निवासी मनोज सिंह उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले बचाव अभियान शुरू किया। अर्जुन भुईंया के अनुसार, तेज आवाज सुनने के बाद जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां अफरा-तफरी मची थी। लोगों की चीख-पुकार के बीच एक बच्चे का पैर मलबे में दिखाई दे रहा था।

जमीन की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति दोबारा धंसान की चपेट में आ सकता था। इसके बावजूद अर्जुन ने गड्ढे में उतरने का फैसला किया। इसके बाद दूसरे ग्रामीण भी मदद के लिए आगे आए।बचाव दल के पास आधुनिक उपकरण नहीं थे। ग्रामीणों ने हाथों से मलबा हटाया और एक-एक कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद करीब पांच लोगों को बाहर निकाला गया।

संक्षिप्त समाचार

बिहार में घूसखोर अंचलाधिकारी गिरफ्तार, एसवीयू ने रंगे हाथ दबोचा

पटना, एजेंसी। बिहार की राजधानी पटना से सटे बांका में पटना विशेष निगरानी इकाई यानी ने बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के चान्दन अंचल के अंचल अधिकारी रविकांत कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन से जुड़े एक मामले में दखल-कब्जा दिलाने के एवज में अधिकारी पर दो लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है।

विशेष निगरानी इकाई के अनुसार शिकायतकर्ता सियाराम कुमार, पिता वासुदेव यादव, ग्राम झा, टोला मोरवे, पोस्ट लोहारी, थाना चान्दन, जिला बांका के रहने वाले हैं। उन्होंने एसवीयू पटना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसवीयू की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी अधिकारी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए गिरफ्तार कर लिया।

दरअसल शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि टाइटल सूट केस संख्या 2395/95 में पारित आदेश के तहत संबंधित जमीन पर पीड़ित को दखल-कब्जा दिलाने के लिए चान्दन के अंचल अधिकारी रविकांत कुमार द्वारा दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार तत्काल 20 से 25 हजार रुपये देने की मांग भी की गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष निगरानी इकाई ने शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान अंचल अधिकारी रविकांत कुमार द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसवीयू ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी की गई।

एनडीए और सीडीएस परीक्षा के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 15 प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्त

पटना: बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए की गई है। इनमें एनडीए एंड एनए परीक्षा-II 2026 और सीडीएस परीक्षा-II 2026 शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है।

संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से इन परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को किया जा रहा है। इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए बिहार के अधिकारियों को जिला अधिकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। प्रतिनियुक्त अधिकारियों में नलिन प्रताप राणा और विशाल आनंद विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में ग्रामीण विकास विभाग से हैं। अमित कुमार उपसचिव लघु जल संसाधन विभाग से तथा हर्ष प्रियदर्शी विशेष कार्य पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग से शामिल हैं। राजकिशोर लाल उपसचिव ऊर्जा विभाग से, शंभू नाथ विशेष कार्य अधिकारी पर्यटन विभाग से तथा धीरेंद्र कुमार उपसचिव गन्ना उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी परीक्षा संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐश्वर्या कश्यप विशेष कार्य पदाधिकारी खान एवं भूतत्व विभाग से, स्मृति कुमारी विशेष कार्य पदाधिकारी सहकारिता विभाग से तथा अनिल कुमार उपसचिव डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से हैं। इनकी तैनाती जिला स्तर पर की गई है।

बिहार शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित स्कूलों का मांगा ब्योरा, राहत शिविरों में बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक

पटना, एजेंसी। बिहार में बाढ़ के कारण कई इलाकों में स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से बाढ़ प्रभावित विद्यालयों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। विभाग ने स्कूल भवनों के साथ-साथ शैक्षणिक सामग्री और अन्य संसाधनों को हुए नुकसान का भी आकलन करने का निर्देश दिया है। विभाग का कहना है कि बाढ़ के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में भी बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा विभाग की ओर से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में बाढ़ से प्रभावित विद्यालयों की मौजूदा स्थिति का आकलन कर अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसमें कितने स्कूल प्रभावित हैं, उनकी स्थिति क्या है और बाढ़ के कारण किस स्तर तक नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी शामिल करने को कहा गया है।

बाढ़ ने आशियाना छीना, पर पढ़ाई का जज्बा नहीं,

भागलपुर के राहत शिविरों में शुरू हुई 'डिजिटल पाठशाला'

भागलपुर, एजेंसी। बिहार में गंगा, कोसी और गंडक जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इस भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य के 4,000 से अधिक स्कूल पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं. पटना, मुंगेर, भागलपुर, वैशाली और कटिहार समेत कई जिलों में लाखों बच्चों की शिक्षा पूरी तरह बाधित हो गई है. इन सबके बीच सुकून देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं. बिहार सरकार ने राहत शिविरों में टीवी, डिजिटल तकनीक और अस्थायी पाठशालाओं के जरिए विस्थापित छात्रों की शिक्षा और मनोरंजन की सराहनीय व्यवस्था की है.

गंगा के बढ़ते जलस्तर से भागलपुर का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है. प्रभावित लोगों के रहने के लिए प्रशासन ने राहत शिविरों का बंदोबस्त किया है. बाढ़ग्रस्त नाथनगर क्षेत्र के विस्थापित लोगों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड मैदान में राहत शिविर संचालित किया जा रहा है. इस शिविर में विस्थापित परिवारों को हर संभव बुनियादी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है.

राहत शिविरों में विस्थापित बच्चों की पढ़ाई और मनोरंजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन ने यहां टीवी लगाए हैं, जिससे बच्चे मनोरंजन के साथ पढ़ाई और नई चीजें सीख रहे हैं. टीवी की इस अनोखी सुविधा से शिविर में रह रहे लोग, खासकर जेन-अल्फा पीढ़ी के बच्चे काफी खुश हैं और सरकार के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा कर रहे हैं.

शिविर में टीवी लगने से सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि यह डिजिटल मनोरंजन सुविधा उनके अपने घरों पर भी उपलब्ध नहीं थी. यहां बच्चे और बड़े मिलकर एक साथ फिल्में देख रहे हैं और खुशी-खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं.

भागलपुर के एडीएम आपदा कुंदन कुमार ने बताया कि विस्थापित लोगों के मनोरंजन के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड राहत शिविर में एलसीडी टीवी की व्यवस्था की गई है. प्रशासन की योजना बच्चों के मनोरंजन के साथ-साथ उनकी निरंतर पढ़ाई सुनिश्चित करने की भी है. इसके लिए शिविर में एक अस्थायी पाठशाला भी शुरू की गई है, जहाँ बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाया जा रहा है.

'भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित लोगों के लिए बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर राहत शिविर बनाया गया है. शिविर में बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, स्वच्छ शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय और आंगनबाड़ी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है

राहत शिविर में की गई इस विशेष व्यवस्था से बच्चों को यह बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि उनका स्कूल बंद है. आपदा के इस कठिन समय में भी उनकी शिक्षा लगातार जारी रहेगी. प्रशासन का यह कदम बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत रखने और उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए उठाया गया है, जिससे उनका शैक्षणिक नुकसान न हो.

भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रभावित लोगों के लिए बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के भीतर एक बड़ा राहत शिविर बनाया गया है. इस शिविर में बाढ़ पीड़ितों के ठहरने के साथ-साथ भोजन, स्वच्छ शौचालय और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे आपदा प्रभावित लोगों को कोई परेशानी न हो.

पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर विस्थापित बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं. बाढ़ पीड़ितों के बच्चों के लिए शिविर के भीतर ही विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इससे छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की देखभाल भी राहत शिविर के सुरक्षित माहौल में आसानी से हो पा रही है.

बता दें कि बाढ़ के कारण स्कूलों के परिसरों और कक्षाओं में भारी जलजमाव हो गया है. इस वजह से शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है. कई ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे या गहरे पानी को पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं. प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद लचर है और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है.

स्कूलों और घरों में किताबें डूबने के बाद भी शिक्षा विभाग ने सितंबर के मध्य से परीक्षाओं के आयोजन का फैसला लिया है. विभाग द्वारा अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षाएं आयोजित करने के इस निर्णय से छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. आपदा के इस दौर में बिना किसी तैयारी के परीक्षा लेना मानसिक तनाव को और बढ़ा रहा है.

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसः उत्कट जिजीविषा और संघर्ष की मिसाल

पटना, एजेंसी। बिहार उत्कट जिजीविषा और संघर्षों को आत्मसात कर उनसे जीतने वाला प्रदेश है. प्रदेश के लोगों ने कई मौकों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. हम बिहारियों की संघर्ष क्षमता हमे अलग पहचान दिलाती है. शायद यहीं कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग जहां जिंदगी से जल्द हार मान रहे हैं, वहीं बिहारी डट कर मुकाबला कर कहा है. विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर इसी पर बात करेंगें.

इस बात की तस्दीक आंकड़ें भी करते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर जहां आत्महत्या के आकड़ें चौंका देने वाले हैं तो बिहार आत्महत्या के मामले में निचले पायदान पर है. प्रदेश के कोने-कोने से ऐसी कई कहानियां निकल कर सामने आई हैं जो बताती है कि अकेलेपन से इस जंग में बिहार कहीं न कहीं देश के मुकाबले जीत दर्ज करने में सफल रहा है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इसके पीछे मजबूत पारिवारिक व्यवस्था भी अहम भूमिका निभाती हैं. बिहार के अंजनी पांडे की कहानी मुश्किल दौर से निकलने की मिसाल है. स्टार्टअप में असफल होने के बाद कुछ साल पहले उनके मन में आत्महत्या का ख्याल आया था. वह काफी निराश हो गए थे. लेकिन उनके चाचा रघुवर पांडे ने उनका हौसला बढ़ाया और मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया. अंजनी ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा. आज उनका सालाना कारोबार करीब 5 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और वह एक सफल व्यवसायी बनने की राह पर हैं. अंजनी कहते हैं कि शुरुआती दौर में हमने नौकरी के लिए तैयारी की लेकिन सफलता नहीं मिली और फिर उसके बाद अपना ध्यान स्टार्टअप की ओर लगाया स्टार्टअप में भी सफलता नहीं मिलने के बाद निराश हो गया और मन में आत्महत्या जैसे ख्याल भी आने लगे. परिवार के लोग और चाचा जी ने हमारा साथ दिया जिसकी बदौलत हम फिर संघर्ष के लिए आगे बढ़े और हमारा स्टार्टअप आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है.

बिहार का 'अमेरिकन हाउस'! छत और बेडरूम तक जाती है कार, खरीदेंगे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी?

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसा आलीशान मकान है, जिसकी बनावट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इस मकान में हर फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा है. आप अपनी कार लेकर सीधे बेडरूम तक पहुंच सकते हैं. स्थानीय लोग इसे 'अमेरिकन हाउस' और 'डॉलर विला' के नाम से जानते हैं. दूर-दराज से लोग इस मकान को देखने और यहां सेल्फी लेने तक पहुंचते हैं. इसके अलावा चर्चा ये भी है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी इच्छा जताई है.

मुजफ्फरपुर में इस आलीशान अमेरिकन हाउस की बनावट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. जिले के रामदयालु इलाके में करीब दस बीघे में फैली यह प्रॉपर्टी अपनी भव्यता और अनोखी वास्तुकला के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. स्थानीय लोग इसे 'अमेरिकन हाउस' और 'डॉलर विला' के नाम से जानते हैं. दूर-दराज से लोग इस मकान को देखने और यहां सेल्फी लेने तक पहुंचते हैं. अमेरिकी शैली में बना यह मकान

अमेरिकी शैली की वास्तुकला और भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

मकान में तीन मंजिल हैं और हर फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा बताई गई है. इसकी सबसे खास बात यहां बनी विशेष रैंप है, जिस पर कार सीधे ऊपरी मंजिल, छत और बेडरूम तक पहुंच सकती है. मकान में कुल 14 कोठियां बनाई गई हैं. इसके अलावा परिसर में फाउंटेन, स्विमिंग पूल, बड़ा गार्डन और ऊपर कॉटेजनुमा बैठने की जगह भी है जिसे गजिबू भी कहा जाता है, जहां बैठकर लोग आराम कर सकते हैं.

मकान के मालिक अजय सिंह के चाचा रणबीर सिंह के मुताबिक 2012 में शुरू हुआ इसका निर्माण 2016 में पूरा हुआ. अजय सिंह वर्ष 1987 में अमेरिका गए थे और इसके बाद वे परिवार के साथ वहीं बस गए. अमेरिका में वे परफ्यूम का कारोबार करते हैं. उनका एक बेटा और एक बेटी है. रणबीर सिंह बताते हैं कि घर के निर्माण और डिजाइन में उनके रिश्तेदार आर्किटेक्ट इंजीनियर विपुल सिंह की भी भूमिका रही.

'सबसे खास बात यहां बनी विशेष रैंप है, जिस पर कार सीधे ऊपरी मंजिल, छत और बेडरूम तक पहुंच सकती है. मकान में कुल 14 कोठियां बनाई गई हैं. इसके अलावा परिसर में फाउंटेन, स्विमिंग पूल, बड़ा गार्डन और ऊपर कॉटेजनुमा बैठने की जगह भी है जिसे गजिबू भी कहा जाता है, जहां बैठकर लोग आराम कर सकते हैं. उस समय करीब छह करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे '- रणबीर सिंह, मालिक अजय सिंह के चाचा

रणबीर सिंह के मुताबिक, मकान के निर्माण के दौरान उस समय करीब छह करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे. हालांकि, परिवार के एक सदस्य ने पूरी प्रॉपर्टी और निर्माण पर इससे काफी अधिक राशि खर्च होने की बात बताई है. उन्होंने बताया कि घर की डिजाइन तैयार करते समय परिवार के आर्किटेक्ट सदस्य विपुल ने विशेष योजना के तहत इसका नक्शा तैयार किया था.

मकान की खासियत बताते हुए रणबीर सिंह बताते हैं कि रैंप इस तरह बनाई गई है कि वाहन को सीधे ऊपरी हिस्से तक ले जाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि मकान में फाउंटेन, स्विमिंग पूल, गार्डन और ऊपर कॉटेजनुमा स्थान बनाया गया है

सहरसा एयरपोर्ट के विकास को मिली रफ्तार, एएआई ने जारी किया 42.52 करोड़ का टेंडर

सहरसा, एजेंसी। बिहार के सहरसा को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर इस पहल की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि सहरसा हवाई अड्डे के विकास एवं उन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ढ्ढ) ने टेंडर जारी कर दिया है। इससे पूरे कोसी क्षेत्र को हवाई सुविधा मिलने की राह आसान हुई है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सहरसा एयरपोर्ट के विकास और उन्नयन के लिए 42 करोड़ 52 लाख का टेंडर जारी किया है। यह कदम एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने और नियमित उड़ानें शुरू करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। टेंडर जारी होने के बाद निर्माण प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। रनवे विस्तार के लिए राज्य सरकार पश्चिमी छोर की ओर लगभग 12 एकड़ (4।95705 हेक्टेयर) जमीन उपलब्ध करा रही है। इस भूमि अधिग्रहण के लिए अप्रैल में ही 147 करोड़ 76 लाख 56 हजार 180 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। अधिकांश भूमि आवासीय है और इसकी लागत राज्य सरकार वहन कर रही है। सहरसा हवाई अड्डे को केंद्र की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना में शामिल करने के लिए 30 जून 2025 को बिहार सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच समझौता हुआ था। इस परियोजना से सीमांचल और कोसी क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। जिला भू-अर्जन विभाग ने रनवे विस्तार के लिए 174 रैयतों की सूची जारी की है। कहरा अंचल के राजस्व थाना बनगांव (थाना संख्या 190) के नरियार मौजा में 67 खेसरा चिह्नित किए गए हैं। दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची तैयार कर विधिवत अधिग्रहण आगे बढ़ाया जा रहा है।

डाक विभाग पितृ पक्ष मेले का लिफाफा और पोस्टकार्ड करेगा जारी

गयाजी, एजेंसी। बिहार की मोक्ष भूमि गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला 2026 को लेकर डाक विभाग ने बड़ी पहल की है. पितृ पक्ष के महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष पोस्टकार्ड और लिफाफे जारी किए जाएंगे, जिन पर मेले से संबंधित लोगो और जानकारी अंकित होगी. मेला अवधि के दौरान हर पोस्टकार्ड, लिफाफे और बंडल पर पितृ पक्ष लोगो रहेगा. इस संबंध में डाक विभाग ने जिला पदाधिकारी को सूचित कर दिया है.

पितृपक्ष मेला के आधिकारिक लोगो को गया की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस सुंदर और सार्थक लोगो में मुख्य रूप से सनातन परंपरा के प्रतीक पिंडदान (पिंड की आकृति), तर्पण करते हुए हाथ, मोक्ष भूमि गयाजी का ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर, पवित्र फल्गु नदी की लहरें और गया की पहचान अक्षयवट वृक्ष को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है.

गयाजी शहर को नया रूप देने के लिए स्थानीय बच्चों की प्रतिभा का उपयोग किया गया है. बच्चों के बीच प्रतियोगिता से पितृ पक्ष मेले का आधिकारिक लोगो चुना गया है. मुख्य लोगो के अलावा नौ अन्य चयनित लोगो प्रचार में इस्तेमाल होंगे. 'पेंट द सिटी' पहल के तहत 27 समूह दीवारों, घाटों और चौराहों पर पौराणिक कहानियों की पेंटिंग बना रहे हैं. डाक विभाग विशेष लोगो वाले लिफाफे और कार्ड जारी करने के साथ चलंत एटीएम की सुविधा भी देगा. ये मोबाइल एटीएम मेला क्षेत्र में घूम-घूमकर काम करेंगे, जिन पर डाक विभाग के कर्मचारी तैनात रहेंगे. इससे श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में ही नकदी की सुविधा मिलेगी और ठगी-फ्रॉड से बचाव होगा. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने इसे नई और अच्छी पहल बताया है.

पितृ पक्ष महासंगम 2026 का आगाज 25 सितंबर से हो रहा है और 10 अक्टूबर तक चलेगा. देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन और सरकार लगातार तैयारी कर रही है. दूसरे राज्यों में भी पितृ पक्ष की धार्मिक महत्ता, सुविधाओं और व्यवस्थाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की मोक्ष कामना लेकर पहुंचें.

जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के अनुसार पितृ पक्ष से पहले पूर्व की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. तैयारी के लिए कई कोषांग गठित किए गए थे, जो लगभग अंतिम चरण में हैं. इस बार कुछ नए प्रयोग भी किए जाएंगे. पेयजल, सफाई, प्रकाश, ट्रैफिक और सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.

डीएम ने बताया कि मेला में पहली बार ट्रायल बेस्ड एआई टूल्स का उपयोग होगा. जिओ फेसिंग ऐप से सटीक संख्या का पता चलेगा और आने वाले लोगों के चेहरे ऐप में कैद होंगे.

झारखंड से आकर बिहार में तबाही मचाती है पुनपुन नदी, टापू बन जाता है गांव

पटना, एजेंसी। बिहार में हर साल गंगा, कोसी, गंडक और महानंदा समेत कई नदियां भारी तबाही मचाती हैं. इस तबाही में एक प्रमुख नाम पुनपुन नदी का भी शामिल है. वर्तमान समय में पुनपुन नदी ने बिहार के कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है. पटना से पुनपुन नदी की दूरी करीब 11-12 किलोमीटर है. इसके पास स्थित मसौढ़ी और पुनपुन के इलाकों में बाढ़ से बुरा हाल है. यहां लगभग 25-30 हजार लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं.

पुनपुन नदी और दरधा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि इसका पानी आस-पास के रिहायशी इलाकों में फैल गया है. बाढ़ के पानी के कारण स्थानीय लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. बाढ़ के कारण लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं. कई जगहों पर लोगों को अपने और अपने परिवार के पेट के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है.

मसौढ़ी में पुनपुन नदी का पानी अब खेतों से निकलकर शहर के घरों में घुस गया है. पुनपुन शहर के जाहिदपुर वार्ड में करीब 30 से 40 घर चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं. पूरे क्षेत्र की बात करें तो करीब

2000 घर बाढ़ से प्रभावित होंगे. हालत यह है कि लोग अपने ही घर में जल कैदी बनकर रहने को मजबूर हैं. घर से बाहर निकलने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है. इस पानी की जद में विकास कुमार का भी घर आ गया है.

इलाके में यातायात पूरी तरह ठप है. लोग लकड़ी, टायर और ड्रम को जोड़कर बनाई गई जुगाड़ नाव के सहारे जिंदगी काट रहे हैं. कहीं रस्सी के सहारे तो कहीं बांस की चचरी पुल बनाकर लोग बाजार तक पहुंच रहे हैं. रोजमर्रा का जरूरी सामान लाने के लिए लोगों को इसी जान जोखिम भरी नाव पर सवार होना पड़ता है. कई बार ड्रम पलटने से लोग पानी में गिर जाते हैं. इससे हमेशा बड़े हादसे का डर बना रहता है.

बाढ़ का पानी घरों में और मोहल्ले में बंद है. इस कारण पानी से अब तेज दुर्गंध आने लगी है. स्थानीय लोगों को पूरे इलाके में महामारी फैलने का बड़ा डर सता रहा है. जाहिदपुर के विकास कुमार, मंजू देवी, वीणा देवी, मंगल प्रसाद, रवि कुमार, कृष्ण प्रसाद और बुधन प्रसाद ने अपना दर्द साझा किया. उन्होंने बताया कि इस बाढ़ में आज तक कोई उनकी सुध लेने नहीं आया. पीड़ितों का कहना है कि नेता और मंत्री तो बहुत दूर की बात है, स्थानीय वार्ड पार्षद तक यह पूछने नहीं आए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं चुनाव में वोट मांगने सब घर-घर आते हैं. आज जब घर पानी में डूबा है, तो कोई देखने वाला नहीं है.

'चुनाव के वोट मांगने सब आते हैं. लेकिन इस बार इस आपदा में अभी तक कोई भी हमें देखने नहीं आया है. घर से निकलना मुश्किल हो गया है. कई दिन से लोग घर में ही कैद हैं. जरूरी सामान के लिए किसी तरह लकड़ी का बोर्ड बनाकर बाहर निकल रहे हैं.'

लोग बताते हैं कि पुनपुन नदी में आई बाढ़ का जलस्तर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है. इसके बावजूद पीड़ितों का दर्द बढ़ गया है. कुछ दिन पहले सामुदायिक रसोई घर चलाकर प्रशासन ने उन्हें भोजन तो दिया था, लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी कम हो गया है, उसके बाद प्रशासन ने भोजन देना बंद कर दिया. बाढ़ में घर टूट चुके हैं. टूटे हुए घरों ने लोगों को बेघर कर दिया है.

संक्षिप्त समाचार

कम उम्र में हार्ट अटैक के जोखिम पर मंथन

लखनऊ, एजेंसी। कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। तंबाकू, मोटापा, तनाव, व्यायाम की कमी, फास्ट फूड के साथ बीपी, डायबिटीज और बढ़ा कोलेस्ट्रॉल इसका खतरा बढ़ा रहे हैं। पीजीआई में बृहस्पतिवार को केजीएमयू के पूर्व छात्र और अमेरिका में रह रहे फिजिशियन व फिल्म निर्माता डॉ. निर्मल जोशी और डॉ. रेनू जोशी की डॉक्यूमेंट्री द ब्राउन हार्ट की स्क्रीनिंग हुई।

करीब 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में दक्षिण एशियाई लोगों में कम उम्र में हार्ट अटैक के कारणों और जोखिमों को बताया गया। स्क्रीनिंग के बाद विशेषज्ञों ने शुरुआती लक्षण, जांच और बचाव से जुड़े सवालों के जवाब दिए।

पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. आदित्य कपूर ने बीपी, ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, वजन और कमर के घेरे की नियमित जांच की सलाह दी। डॉ. रूपाली खन्ना ने महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण समय पर पहचानने पर जोर दिया। निदेशक डॉ. आरके धीमन ने व्यायाम, खानपान और तनाव पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि 2022 में दुनियाभर में करीब 1.98 करोड़ मौतें हृदय संबंधी बीमारियों से हुईं।

फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 25 हजार रुपये समेत बैग लूटा

बरेली, एजेंसी। केरा-सोरहा मार्ग पर बृहस्पतिवार रात फाइनेंस कंपनी के सेल्स कलेक्शन कर्मचारी विजयपाल को लूट लिया गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने तमंचे दिखाकर उनका बैग छीन लिया। बैग में 25 हजार रुपये नकदी, दो मोबाइल फोन और एक टैबलेट था। इसके अतिरिक्त, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज भी थे। विजयपाल धौराटांडा से घर लौट रहे थे। लघुशंका के लिए स्कूटी रोकने पर बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। देर रात तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा सका है। मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

जरपा मोहनपुर गांव की सड़क के लिए एक करोड़ 49 लाख रुपये स्वीकृत

बरेली, एजेंसी। जरपा मोहनपुर गांव तक जाने वाली बदहाल सड़क के निर्माण के लिए एक करोड़ 49 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। ग्रामीण लंबे समय से पक्की सड़क की मांग कर रहे थे। बरसात में गड्ढों और जलभराव से आवागमन में बड़ी परेशानी होती थी। सड़क निर्माण न होने से नाराज ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी किया था। इस बहिष्कार के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर गया। जमीन संबंधी अड़चनें भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से दूर हुईं। विधायक डॉ. एमपी आर्य ने बताया कि बारिश के बाद सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाएगा। एसडीएम सचिन कुमार ने बताया कि सड़क को कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है। बारिश का समय है। अभी निर्माण संभव नहीं है। बारिश के बाद सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है।

जांच के घेरे में सौ से ज्यादा दिव्यांग प्रमाणपत्र, दिल्ली पुलिस को सौंपे

बरेली, एजेंसी। फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र मामले में आउटसोर्सिंग कर्मचारी कुलदीप की भूमिका सामने आने के बाद अब उसके जरिए जारी करीब सौ से ज्यादा दिव्यांग प्रमाणपत्र जांच के घेरे में आ गए। सीएमओ कार्यालय ने दिल्ली पुलिस को तीन बंडल में प्रमाणपत्र संबंधित अभिलेख सौंपे हैं।

इनमें दिव्यांगों के आवेदनपत्र, पहचानपत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज शामिल हैं। सभी रिकॉर्ड जांच में शामिल कर लिए गए हैं। नोडल डॉ. राकेश ने बताया कि जो अभिलेख मांगे थे वह दे दिए गए हैं। दूसरी ओर, कुलदीप की कार्यप्रणाली की पड़ताल में पता चला कि वह सीएमओ कार्यालय के दिव्यांग शिविर के अलावा तहसील दिवस में जाता था। दिव्यांगता आवेदन पत्र की जांच, फाइल को चिकित्सक के पास परीक्षण के लिए पहुंचाने में शामिल था। लिहाजा, तैनाती के दौरान बने प्रमाणपत्र में उसकी भूमिका का पता लगाया जा रहा है। इसके लिए प्रमाणपत्रों में लगाए गए दस्तावेज और चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया का भी मिलान कराया जाएगा।

सांप, चिड़िया जैसे सभी जानवरों का मैप पर मिलेगा पता; गूगल डॉक जारी

वाराणसी, एजेंसी। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू को जैव विविधता परिसर का दर्जा दिलाने के लिए पक्षी और वन्यजीव सर्वेक्षण शुरू किया गया। सांप, चिड़िया समेत परिसर में दिखाई देने वाले उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जीवों का डॉक्यूमेंट तैयार होगा। इनका पता गूगल मैप पर भी मिलेगा।

इनके वैज्ञानिक नाम से लेकर आवास की जानकारियां मिलेंगी। अगले एक साल यानी 30 सितंबर 2027 तक सर्वे कर आंकड़े जुटाए जाएंगे। बीएचयू परिसर में मौजूद पक्षियों और वन्यजीवों की विविधता के साथ उनके वितरण का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय की हॉर्टिकल्चर यूनिट की ओर से ये सर्वे किया जाएगा। पूरे 1300 एकड़ परिसर में दिखाई देने वाले वन्यजीवों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी जानकारियां सहेजी जाएंगी।

सर्वे में बीएचयू के विद्यार्थी, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी, परिसर में रहने वाले लोगों के साथ ही विश्वविद्यालय समुदाय के कई सदस्य भाग ले सकते हैं। चयन होने पर फोटोग्राफर का नाम 'बीएचयू बायोडायवर्सिटी बुक' में शामिल किया जाएगा। इसके लिए हॉर्टिकल्चर यूनिट की ओर से गूगल फॉर्म जारी किया गया है। जीवों की तस्वीरें यहां अपलोड की जा सकती हैं।

गूगल मैप पर देना होगा स्क्रीन शॉट- हर वन्यजीव के पड़ताल की जानकारी अलग-अलग जमा करनी होगी। प्रतिभागियों को जीव का सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम, तस्वीर लेने की तारीख और समय, स्थान और गूगल मैप पर उस स्थान का स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा।

फोटो चयनित होने पर मिलेगा प्रमाणपत्र

मान्य प्रविष्टियों यानी फोटो चयनित होने पर प्रतिभागी को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। हर एक श्रेणी में चयनित सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों के लिए नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। चयनित तस्वीरों को फोटोग्राफर के नाम के साथ प्रस्तावित 'बीएचयू बायोडायवर्सिटी बुक' में शामिल किया जाएगा।

एआई या इंटरनेट फोटो होगी अस्वीकृत

हॉर्टिकल्चर यूनिट की ओर से निर्देश दिया गया है कि प्रतिभागी स्पष्ट और मूल तस्वीरें ही अपलोड करें। तस्वीरें स्वयं से ही बीएचयू परिसर में खींची गई हो। एआई, इंटरनेट, सोशल मीडिया, किताब या अन्य स्रोत से प्राप्त तस्वीरें स्वीकार नहीं की जाएंगी। वन्यजीवों की तस्वीर लेते समय उन्हें पकड़ने, खिलाने, पीछा करने या किसी अन्य तरह से परेशान करने से बचने की अपील की गई है।

बाढ़ में 10 हजार एकड़ फसल डूबी, 20 गांवों के सात हजार लोग प्रभावित, स्कूल बंद

लखनऊ, एजेंसी। लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से इटौंजा, बख्शी का तालाब और माल क्षेत्र के 20 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इससे करीब सात हजार लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और जलभराव से 10 हजार एकड़ में धान और सब्जियों की फसल बर्बाद होने का दावा किया गया है। पशुओं के चारे की व्यवस्था करना भी ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो गया है। बाढ़ प्रभावित गांवों में सुल्तानपुर, बहादुरपुर, हीरापुरवा, लासा, अकड़रिया खुर्द, अकड़रिया कला, दुघरा, राजापुर, करौंदी, मलूकपुर, जमखनवा, जमखनवा पुरवा, मल्लाहन खेड़ा, कठवारा, बदैयां, टिकरी और बहरौरा शामिल हैं। खेतों में धान के अलावा भिंडी, तोरई, लौकी, कद्दू, बैंगन, खीरा और मिर्च की फसलें भी पानी में डूब गई हैं। अकड़रिया गांव का प्राथमिक विद्यालय बंद करना पड़ा है। जलमग्न रास्तों से आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। किसानों ने मांगा मुआवजाः किसान धर्मेंद्र कुमार कश्यप ने बताया कि दो बीघा धान और तीन बीघा उड़द की फसल डूब गई। देवी दयाल की करीब साढ़े पांच बीघा धान की फसल भी बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि हर साल फसल बर्बाद होने पर मुआवजे का आश्वासन मिलता है लेकिन भुगतान नहीं होता। उन्होंने फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है।

मानसिक संकट के संकेत पहचानें, खुलकर करें बातचीत

गोरखपुर, एजेंसी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक परेशानियों के प्रति जागरूक किया गया। विश्वविद्यालय में 'आत्महत्या पर बदलता नजरिया : बातचीत की शुरुआत' विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें विद्यार्थियों को तनाव, भावनात्मक संकट के संकेत पहचानने और समय रहते मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया।

मनोचिकित्सक डॉ. शांतनुप्रकाश अग्रवाल ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और भावनात्मक संकट के शुरुआती संकेतों को पहचानने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानसिक परेशानी को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं नशामुक्ति विशेषज्ञ डॉ. नितेश मिश्रा ने शैक्षणिक दबाव, व्यक्तिगत चुनौतियों और भावनात्मक कठिनाइयों से सकारात्मक ढंग से निपटने के उपाय बताए।

कार्यक्रम में जागरूकता आधारित वृत्तचित्र भी दिखाया गया। विद्यार्थियों को समझाया गया कि संकट में घिरे व्यक्ति की बात बिना निर्णय और दोषारोपण के सुनी जाए तथा जरूरत पड़ने पर परिवार, मित्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों से सहायता ली जाए। विशेषज्ञों ने कहा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि जागरूकता और साहस का प्रतीक है। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग और भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर नारायण सिंह ने अध्यक्षता की। संयोजक डॉ. मिलिंद राज आनंद रहे। आयोजन में विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी शामिल हुए।

विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य उनकी शैक्षणिक और व्यक्तिगत सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। तनाव या भावनात्मक परेशानी को छिपाने के बजाय उसके बारे में बात करना जरूरी है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए ऐसा सहयोगी वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां वे अपनी समस्याएं बिना संकोच साझा कर सकें।

-प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा,
कुलपति, एमएमएमयूटी

चार दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल, तीन कंपनियां ब्लैकलिस्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन की ओर से खरीदी गईं चार दवाएं गुणवत्ता जांच में मानकों पर खरी नहीं उतरीं। इनमें एथैम्सिलेट 500 एमजी, इबुप्रोफेन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड 500 एमजी और क्लोट्रिमेजोल शामिल हैं। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कॉरपोरेशन ने दवाओं को ड्रग वेयरहाउस से वापस मंगाने के निर्देश दिए हैं। संबंधित कंपनियों को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। कॉर्पोरेशन सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं खरीदकर प्रदेश के अलग-अलग ड्रग वेयरहाउस में भेजता है। अस्पतालों में आपूर्ति से पहले कराई गई जांच में दवाएं फेल मिलीं। मेरठ की डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स की एथैम्सिलेट और इबुप्रोफेन गुणवत्ता जांच में फेल हुईं। एथैम्सिलेट बैच नंबर डीटीडी-034, डीटीडी 078, डीटीडी 075 जांच में फेल हो गई है।

खुद को घोड़े का इंजेक्शन लगाकर दौड़े युवक, फिर जो हुआ; चिकित्सक भी रह गए दंग

आगरा, एजेंसी। यूपी के आगरा जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे दो युवकों ने ऐसा काम किया कि चिकित्सक भी हैरान रह गए। दोनों युवकों ने घोड़ों को दिया जाने वाला इंजेक्शन खुद को लगा दिया। जिससे दोनों युवकों की हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। यहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। चिकित्सकों की मानें तो इस इंजेक्शन से युवकों की जान भी जा सकती थी।

मामला आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र का है। दौड़ते समय थकान का अहसास कम करने के लिए घोड़ों को लगाया जाने वाला स्टेरॉयड इंजेक्शन आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों ने दौड़ में बेहतर प्रदर्शन के लिए लगवा लिया। दोनों युवक दोस्त हैं। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे तबीयत बिगड़ने पर उनके साथी उन्हें सीएचसी खेरागढ़ लेकर पहुंचे। युवकों के पास इंजेक्शन की खाली शीशी भी थी।

उन्होंने बताया कि तीन एमएल इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीएचसी में करीब दो घंटे उपचार के बाद दोनों की हालत में सुधार हुआ। इसके बाद साथी उन्हें घर ले गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरके सिंह ने बताया ऐसे इंजेक्शन शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। अधिक मात्रा में लगाने से जान भी जा सकती है। युवाओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए

दिसंबर बाद बकाया गृहकर पर ब्याज नहीं माफ कर पाएगा नगर निगम

लखनऊ, एजेंसी। नगर निगम दिसंबर के बाद बकाया गृहकर पर ब्याज नहीं माफ करेगा। अभी करीब ढाई लाख बकायेदारों का 223 करोड़ रुपये ब्याज माफ किया जा रहा है। 15 दिसंबर को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) समाप्त होने के बाद नगर निगम में ब्याज माफी पर रोक लग जाएगी। फिर ब्याज तभी माफ होगा जब शासन आदेश करेगा। इसका कारण है कि नगर निगम अधिनियम में ब्याज माफी की व्यवस्था नहीं है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय का कहना है कि पूरे प्रदेश के किसी नगर निगम में बकाया गृहकर पर ब्याज माफ करने की व्यवस्था नहीं है। अभी उनका ब्याज माफ किया जाता है जिनका गृहकर संशोधित होता है या पहली बार इसका निर्धारण होता है। ऐसे में गलत निर्धारण पर संशोधन तो होगा पर बकाये पर ब्याज लगेगा। ओटीएस में आ रहे भवनस्वामियों पर ब्याज सहित करीब 650 करोड़ रुपये गृहकर बकाया है। इसमें से करीब 223 करोड़ रुपये ब्याज है।

अभी नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर अपने फायदे के लिए गृहकर को कम-ज्यादा करते हैं तो उसकी जानकारी नगर निगम तक ही सीमित रहती है। हालांकि, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। शासन के आदेश पर गृहकर का पूरा डाटा सॉफ्टवेयर ई नगर सेवा पर भी शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में कोई बदलाव होगा तो शासन के अधिकारी भी इसे देख सकेंगे।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने बताया कि अब पूरे प्रदेश में गृहकर का एक सॉफ्टवेयर ई नगर सेवा होगा। इसके जरिये गृहकर निर्धारण और नामांतरण का काम होगा।

पीएनजी कनेक्शन के लिए अक्तूबर से शुरू होगा पोर्टल

अलीगढ़, एजेंसी। किफायती पाइपलाइन गैस (पीएनजी) का कनेक्शन लेने की प्रक्रिया अक्तूबर महीने से पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। इसके लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिये शहर के प्रमुख इलाकों में रहने वाले लोग घर बैठे ही पीएनजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इंडियन ऑयल अदाणी गैस के एरिया सेल्स मैनेजर आलोक कुमार गिरि के अनुसार, शहर के लगभग 10 प्रमुख क्षेत्रों में पीएनजी की मुख्य पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। इनमें इंजीनियर कॉलोनी, ओजोन सिटी, सांगवान सिटी, स्वर्ण जयंती नगर, स्थानीय अपार्टमेंट और कयामपुर समेत कई अन्य रिहायशी इलाके शामिल हैं।

अब तक 2100 कनेक्शन जारी- कंपनी की ओर से अब तक शहर में कुल 2100 पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वर्तमान में बिछाई जा चुकी लाइनों के माध्यम से 3500 और नए कनेक्शन दिए जाने की योजना है। पोर्टल शुरू होने के बाद इन क्षेत्रों के निवासी आसानी से आवेदन कर सकेंगे।

सिलिंडर वापसी की प्रक्रिया भी जारी- पीएनजी नेटवर्क के विस्तार के साथ ही इन इलाकों में एलपीजी गैस सिलिंडर वापस लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। यहां पाइपलाइन से आपूर्ति शुरू हो चुकी है।

सिविल अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शुरू

लखनऊ, एजेंसी। सिविल अस्पताल में बृहस्पतिवार से सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं शुरू हो गईं। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी की सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी, स्ट्रोक यूनिट, न्यूरो सर्जरी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ हुए समझौते के तहत अब संस्थान के विशेषज्ञ सिविल के मरीजों को परामर्श और उपचार देंगे। अस्पताल निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने बताया कि तीनों सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी सप्ताह में एक-एक दिन चलेंगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस व्यवस्था का विस्तार प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों तक होगा। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के बीच समझौते कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं जिला स्तर तक पहुंचाई जाएंगी। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बार-बार केजीएमयू, लोहिया संस्थान और एसजीपीजीआई जैसे संस्थान नहीं आना पड़ेगा। वहीं, इन संस्थानों पर भी दबाव कम होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 70 वर्ष की आयु वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को पुनर्नियुक्ति से सरकारी अस्पतालों में सेवा देने का अवसर दिया जाएगा।

स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं

उपमुख्यमंत्री ने कहा, स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। उन्होंने मास्क लगाने और प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी। साथ ही बुखार या फ्लू जैसे लक्षण होने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में परामर्श लेने की अपील की।

जीवाश्मों का अतीत बताएगा जलवायु का भविष्य

लखनऊ, एजेंसी। करोड़ों साल पुराने जीवाश्म अब सिर्फ धरती के बीते इतिहास के पन्ने नहीं खोल रहे, बल्कि बदलती जलवायु के भविष्य को समझने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। पुराने पौधों, जीवाश्मों, चट्टानों और प्राकृतिक अवशेषों में दर्ज पर्यावरणीय संकेत वैज्ञानिकों को बताते हैं कि हजारों-लाखों साल पहले मौसम, मानसून और समुद्र का स्तर किस तरह बदला था। इन्हीं बदलावों को समझकर वर्तमान जलवायु परिवर्तन के असर को जानने की कोशिश हो रही है।

राजधानी स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बीएसआईपी) अपने 80 साल के शोध सफर में धरती के अतीत को पढ़ते हुए वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को समझने में जुटा है। बृहस्पतिवार को संस्थान के 80वें स्थापना दिवस पर वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ शोध को नई तकनीक से जोड़ने की योजनाओं की जानकारी दी गई।

पुराने जीवाश्मों में छिपे हैं मौसम के संकेत- बीएसआईपी के निदेशक प्रो. महेश जी. ठक्कर ने बताया कि पुराने पौधों, जीवाश्मों, चट्टानों और प्राकृतिक अवशेषों में उस दौर के पर्यावरण की महत्वपूर्ण जानकारी छिपी है। इनके अध्ययन से हजारों-लाखों साल पहले जलवायु और मानसून में हुए बदलावों, समुद्र के स्तर में परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के स्वरूप का पता चलता है। यही अध्ययन आज हो रहे जलवायु परिवर्तन को समझने में भी मदद कर रहा है।

एआई से जुड़ेगा जीवाश्मों का अतीत- 80वें स्थापना दिवस पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. उमेश वी. वाघमारे ने बीएसआईपी में मिशन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यहां एआई और मशीन लर्निंग की मदद से देश की जीवाश्म विरासत का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अलग-अलग स्थानों से मिले जीवाश्मों की जानकारी एक जगह सुरक्षित होने से वैज्ञानिक बड़े स्तर पर उनका अध्ययन कर सकेंगे। प्रो. वाघमारे ने बताया कि बीएसआईपी का शोध अब जीवाश्म और पुराने पौधों तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, जैव विविधता, प्राकृतिक आपदाओं, भू-विरासत और खगोल जीव विज्ञान जैसे विषयों पर भी काम हो रहा है। उन्होंने वर्ष 2027 में लखनऊ में होने वाली 'ढ्ढह्लक्र कांग्रेस' की मेजबानी मिलने पर संस्थान को बधाई दी।

केदारनाथ ने बताया चेतावनी का महत्व- स्थापना दिवस व्याख्यान में आईएमडी के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. आनंद शर्मा ने 2013 की केदारनाथ आपदा का उदाहरण देते हुए कहा कि पहाड़ों में भारी बारिश जैसे खतरों के संकेत समय रहते मिलें और लोगों तक पहुंचें तो जानमाल का नुकसान कम किया जा सकता है।

एप्रोच मार्ग के लिए जमीन का समतलीकरण शुरू

आगरा, एजेंसी। चंबल घाट पर पक्के पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा में पुल को जोड़ने के लिए एप्रोच मार्ग बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को जेसीबी की मदद से एप्रोच मार्ग के लिए जमीन का समतलीकरण कराया गया। बुधवार को किसानों ने खड़ी बाजरा की फसल का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर एप्रोच मार्ग का कार्य रुकवा दिया था। सूचना पर उपजिलाधिकारी बाह विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। किसानों और सेतु निगम के कर्मचारियों के बीच सहमति बनने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की सीमा में एप्रोच मार्ग का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश की ओर जमीन समतलीकरण का काम शुरू होने से एप्रोच मार्ग की प्रक्रिया तेज हो गई है।

संक्षिप्त समाचार

सरकारी जमीन पर नहीं रहेगा मंदिर, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रियदर्शनी विहार अवैध मंदिर के मामले में खारिज की याचिका

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रियदर्शनी विहार में नर्सरी स्कूल के लिए आवंटित जमीन पर बने मंदिर को बनाए रखने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि मंदिर बिना मंजूरी के और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। डीडीए के 2021 के फैसले को रद करने की थी मांग याचिकाकर्ता संस्था ने कोर्ट से डीडीए के 2021 के फैसले को रद करने और वहां बने मंदिर को बनाए रखने की मांग की थी। कोर्ट ने पाया कि यह जमीन मूल रूप से नर्सरी स्कूल के लिए तय की गई थी। इलाके को विकसित कर रहे अमेरिकन एम्बेसी एम्प्लाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने बाद में मंदिर बनाने के लिए जमीन के आवंटन की मांग की थी। 1987 में अलग धार्मिक सोसाइटी बनाने को कहा था डीडीए ने 1987 में सोसायटी से एक अलग धार्मिक सोसायटी बनाने और आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए कहा था। इसके बाद याचिकाकर्ता-सोसायटी बनाई गई। बिना मंजूरी मंदिर निर्माण को कोर्ट ने माना अवैध हालांकि, फैसले के मुताबिक, उसने 1991-92 में बिना जमीन के इस्तेमाल में बदलाव या डीडीए से मंजूरी लिए बगैर अवैध रूप से मंदिर का निर्माण किया।

दिल्ली के कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेंटर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग

नईदिल्ली, एजेंसी। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाना क्षेत्र में कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेंटर के पास फायरिंग की घटना में दो युवक गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल दोनों युवक हाईपर कैफे में पार्टी करके घर लौट रहे थे। वहीं, घायलों की पहचान ल मुरादनगर निवासी अफसर और सीलमपुर निवासी इरशाद के रूप में हुई है। दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और चिकित्सकों के अनुसार, वे खतरे से बाहर हैं। आशंका है रंजिश में वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि हेडगेवार अस्पताल से आनंद विहार थाना पुलिस को दो घायलों के भर्ती होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। दोनों के शरीर के पिछले हिस्से में गोली लगी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कम्युनिटी सेंटर के पास किसी घटना के दौरान दोनों को गोली लगी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस फायरिंग के कारण और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। घायलों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद फायरिंग की पूरी वजह और घटनाक्रम स्पष्ट हो सकेगा।

दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के आसार

नई दिल्ली, एजेंसी। पिछले कई दिनों से राजधानी में मौसम साफ रहने के साथ ही तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। लेकिन, शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदलने और अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान राजधानी में बारिश हो सकती है। बृहस्पतिवार को सुबह से ही धूप खिली रही। बीते छह दिनों में अधिकतम तापमान में नौ डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। पांच सितंबर को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो बृहस्पतिवार को बढ़कर 36.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, पिछले तीन दिनों से उत्तर-पश्चिमी हवा चलने के कारण इस क्षेत्र से मानसूनी गतिविधियां कम हो गई थीं। अब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

ट्रैफिक पुलिस अगर आपकी गाड़ी उठा ले जाए, तो न हों परेशान, बस 1 क्लिक में ऑनलाइन मिलेगी लोकेशन, क्यूआर से भर सकेंगे चालान

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में अब ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी टो कर लेती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। गाड़ी टो होने के बाद उसकी लोकेशन पता करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपग्रेडेड वेबसाइट पर वाहन मालिक ऑनलाइन अपने टो किए गए वाहन की लोकेशन देख सकेंगे। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बृहस्पतिवार को इस नए पोर्टल का शुभारंभ किया।

अपग्रेडेड वेबसाइट पर वाहन मालिक अपने टो किए गए वाहन की लोकेशन ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर उसके खिलाफ जारी चालान की जानकारी भी देखी जा सकेगी। चालान का भुगतान क्यूआर कोड के जरिए करने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

नई वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया है। इसे स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्टल पर ट्रैफिक जाम की रीयल टाइम जानकारी भी उपलब्ध होगी। इसके जरिए वाहन चालक अपने सफर के लिए उपयुक्त रूट की पहचान कर सकेंगे।

वेबसाइट पर सड़क संकेतों और रोड मार्किंग की जानकारी देने वाला इंटरैक्टिव सेक्शन भी जोड़ा गया है। इससे लोग ट्रैफिक नियमों और सड़क संकेतों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

पोर्टल में साइबर सुरक्षा के उपायों को भी मजबूत किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराया जा सके।

वेबसाइट के शुभारंभ के दौरान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ प्रशासनिक इंटरफेस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे सड़क सुरक्षा जागरूकता, नागरिक शिक्षा और नागरिकों की भागीदारी के लिए इंटरैक्टिव केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक), संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक), अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) और डीसीपी मौजूद रहे।

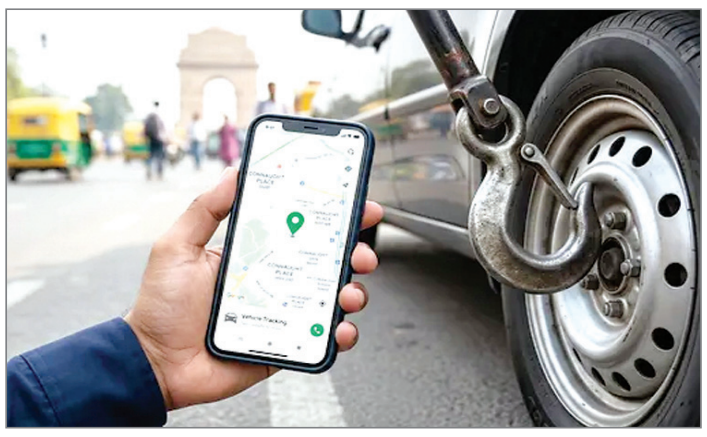

दिल्ली प्रमोद हत्याकांड: नरेला पुलिस शूटरों से करेगी गहन पूछताछ, खुलेंगे कई राज

नईदिल्ली, एजेंसी। बाहरी दिल्ली में नरेला के बाकनेर में प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद की हत्या के मामले में नरेला थाना पुलिस गिरफ्तार शूटरों से पूछताछ करेगी। रोहिणी जिला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नीतिक, दीपक और किशोर को आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब नरेला पुलिस अदालत से प्रोडक्शन रिमांड लेकर तीनों को पूछताछ के लिए अपने कब्जे में लेगी। पुलिस का मुख्य उद्देश्य हत्या की साजिश रचने वाले व्यक्ति, शूटरों को टारगेट की जानकारी देने वाले और वारदात के बाद उन्हें निर्देश देने वालों का पता लगाना है। हथियार उपलब्ध कराने वाले जसवीर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं, जांच में सामने आया है कि शूटर सुपारी लेकर हत्या करते थे और एक वारदात के लिए करीब पांच लाख रुपये तक लेते थे। पुलिस हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरी गिरोह से उनके कथित संपर्क तथा राजस्थान में फरारी के दौरान उन्हें पनाह देने वालों की भी जानकारी जुटाएगी।

शिल्प और संस्कृति की झलक: ब्रिक्स बाजार में अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकेंगे देश भर के कारीगर

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को भारत की समृद्ध शिल्प परंपरा से रूबरू कराने के लिए विशेष ब्रिक्स बाजार सजाया जाएगा।

बाजार में देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और लोक शिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाने के साथ स्थानीय कारीगरों की हुनरमंदी को अंतरराष्ट्रीय मंच देना है। ब्रिक्स बाजार में अलग-अलग राज्यों के शिल्प की अपनी अलग पहचान नजर आएगी। कहीं मिट्टी और लकड़ी से तैयार कलाकृतियां आकर्षित करेंगी तो कहीं हाथ से बुने वस्त्र, पारंपरिक आभूषण, धातु शिल्प और सजावटी सामान भारतीय कारीगरी की बारीकी बयां करेंगे। बाजार में देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े शिल्प को इस तरह प्रस्तुत किया जाएगा कि विदेशी मेहमान एक ही स्थान पर भारत की विविध कला परंपराओं को करीब से देख सकें। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके मद्देनजर प्रमुख म्यूजियम जैसे सुप्रीम कोर्ट स्थित मेट्रो म्यूजियम और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र को 13 सितंबर तक आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। सुरक्षा कारणों से इन स्थानों पर पर्यटकों और अन्य आगंतुकों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मेट्रो म्यूजियम और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली आने वाले पर्यटकों के पसंदीदा स्थानों में शामिल हैं। सामान्य दिनों में यहां दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। छुट्टियों और सप्ताहांत में बड़ी संख्या में परिवार बच्चों के साथ यहां आते हैं। वहीं, दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों की ओर से भी विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए इन स्थानों पर लाया जाता है।

पत्नी सबीला खातून की हत्या कर बाथरूम में छिपाई लाश, दिल्ली पुलिस ने बिहार से आरोपी पति को दबोचा

नईदिल्ली, एजेंसी। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पत्नी की हत्या कर शव बाथरूम में छिपाने और बेटे को लेकर फरार होने के आरोपी मोहम्मद लाल बाबू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा।

पुलिस को उसके बिहार के सीतामढ़ी स्थित गृह नगर में छिपे होने की आशंका थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, लेकिन वह पहले ही किसी रिश्तेदार के यहां चला गया था। कई संभावित ठिकानों पर दबिश देने के बाद पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, प्रहलादपुर बांगर गांव स्थित मकान नंबर 416 के बाथरूम से 22 वर्षीय सबीला खातून का शव 29 अगस्त को बरामद हुआ था। आशंका है कि मोहम्मद लाल बाबू ने घटना से 1-2 दिन पहले सबीला की हत्या की थी। हत्या के बाद शव को बाथरूम में छिपाकर वह अपने कुछ माह के बेटे को लेकर फरार हो गया।

शव बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपित के बिहार भागने की जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, आरोपित बार-बार अपना ठिकाना बदलकर टीम को गुमराह करता रहा। आखिरकार बृहस्पतिवार को उसे दबोच लिया गया।

2 साल पहले किया था निकाहल्ल

वहीं, जांच में सामने आया है कि सबीला और मोहम्मद लाल बाबू ने करीब दो साल पहले निकाह किया था। शादी के बाद से ही दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है।

पुलिस आरोपित से पूछताछ कर घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। वहीं, मृतका के भाई गुलाब का कहना है कि बहन के घर पहुंचने पर उसे घटना की जानकारी हुई और उसने ही पुलिस को सूचना दी थी।

मामले में एक महिला की भूमिका की हो रही जांच

भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस को जानकारी मिली है कि घटना के समय वह घर में मौजूद थी। उसकी पहचान और मोहम्मद लाल बाबू से उसके संबंधों के बारे में पता लगाया जा रहा है। साथ ही, फरारी के दौरान आरोपी कहां-कहां रहा और किन लोगों ने उसे शरण दी, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस पूछताछ के बाद हत्या की वजह और पूरे घटनाक्रम का पता चलने की उम्मीद है।

तपती धरती, उबलते समंदर: अगस्त बना इतिहास का सबसे गर्म महीना, पूर्वी यूरोप में गंभीर सूखे की स्थिति

जेनेवा, एजेंसी। वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। यूरोपीय संघ की प्रमुख निगरानी संस्था कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (सी3एस) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 जुलाई 2023 के साथ संयुक्त रूप से इतिहास का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। इस दौरान दुनिया का औसत वायु तापमान 16.96 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1991-2020 के औसत से 0.85 डिग्री सेल्सियस और पूर्व-औद्योगिक काल (1850-1900) की तुलना में 1.65 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह अप्रत्याशित गर्मी जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, गैस) के जलने से वायुमंडल में लगातार बढ़ रही ग्रीनहाउस गैसों और भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सक्रिय हो रही मजबूत अल नीनो परिस्थितियों का मिला-जुला नतीजा है। महासागरों का तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर है। 60 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री उत्तर के बीच गैर-ध्रुवीय महासागरों का औसत सतही तापमान 21.07 डिग्री दर्ज किया। इसने अगस्त 2023 में बने 20.98 डिग्री के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

जेल में बिगड़ी मादुरो की पत्नी की सेहत: 11 किलो वजन घटा; दिल की बीमारी के बीच घर में नजरबंदी की मांग

अल्बानी, एजेंसी। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी और देश की पूर्व प्रथम महिला सीलिया फ्लोरेस ने अमेरिका की अदालत से जेल से बाहर आने की मांग की है। 69 वर्षीय फ्लोरेस इस समय ब्रुकलिन की संघीय जेल में बंद हैं। उनके वकीलों ने कहा है कि जेल में रहने के दौरान उनकी दिल की बीमारी और बिगड़ गई है। इसलिए उन्हें मुकदमे की सुनवाई तक जेल के बजाय घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। फ्लोरेस के वकीलों ने बुधवार को अदालत में आवेदन दिया है। उन्होंने मैनहट्टन संघीय अदालत के क्षेत्र में घर में रखने की मांग की। अगले साल जून में फ्लोरेस और मादुरो का मुकदमा होना है। घर में रहने के दौरान 24 घंटे सशस्त्र निगरानी की बात कही गई है। वकीलों मार्क डोनेली और एंड्रेस सांचेज ने अदालत को बताया कि घर में रहने की अनुमति मिलने पर फ्लोरेस की कड़ी निगरानी की जाएगी। उनके मुताबिक, उन्हें 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा में रखा जाएगा। उनसे मिलने वाले लोगों को अदालत और संघीय अभियोजकों से मंजूरी लेनी होगी। घर में वीडियो के जरिये निगरानी होगी और उनके फोन कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी वकील जेल से बाहर आने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह खुली आजादी नहीं। फ्लोरेस कई वर्षों से माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स नाम की दिल की बीमारी से जूझ रही हैं। वकीलों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से उन्हें इस बीमारी को संभालने के लिए जरूरी मासिक इंजेक्शन नहीं मिला है। इसके बजाय उन्हें बेबी एस्पिरिन, स्टैटिन और डिल्टियाजेम दी जा रही हैं, जबकि सीने में दर्द होने पर नाइट्रोग्लिसरीन लेने को कहा गया है। फ्लोरेस लगातार रिफ्लक्स और गैस्ट्राइटिस से भी परेशान हैं। जेल में रहते हुए उनके दो दांत निकल चुके हैं। उनका वजन 11.3 किलोग्राम से ज्यादा कम हो गया है। डॉक्टरों ने उन्हें कार्डियक कैथेटराइजेशन कराने की सलाह दी है। फ्लोरेस और उनके पति निकोलस मादुरो को जनवरी की शुरुआत में काराकास स्थित उनके घर से अमेरिकी बलों ने आधी रात की कार्रवाई में हिरासत में लिया था। इसके बाद दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिका ने दोनों पर कोकीन को अमेरिका पहुंचाने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। दोनों ने इन आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है। अलग अदालत में दाखिल एक याचिका में दोनों ने अपने खिलाफ आरोपपत्र खारिज करने की मांग भी की है। उनका कहना है कि किसी विदेशी देश के नेता और प्रथम महिला होने के कारण उन्हें कानूनी छूट यानी इम्युनिटी हासिल है। अभी अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने फ्लोरेस की घर में नजरबंदी की मांग पर जवाब दाखिल नहीं किया है। मैनहट्टन स्थित अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के प्रवक्ता ने भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। जज एल्विन के. हेलरस्टीन ने फ्लोरेस की मांग पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है।वकीलों ने यह भी माना है कि जेल के कर्मचारियों ने फ्लोरेस और मादुरो के साथ बेहद सम्मानजनक व्यवहार किया है और उन्हें जेल तथा अस्पताल में मेडिकल विशेषज्ञों से अच्छी देखभाल मिली है। लेकिन उनका तर्क है कि हिरासत केंद्र में दिल की किसी प्रक्रिया के बाद ठीक होने के लिए जरूरी माहौल नहीं है। अगर कैथेटराइजेशन या आगे कोई दिल की प्रक्रिया होती है, तो फ्लोरेस को स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त समय और बेहतर माहौल की जरूरत होगी।

पुतिन का प्लेन नहीं, कमांड सेंटर: किसमें हैं रूसी राष्ट्रपति पहचानना मुश्किल

मॉस्को, एजेंसी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। लेकिन उनकी यात्रा में सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातें ही चर्चा में नहीं हैं। उनके भारत आने के तरीके ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। पुतिन जिस खास विमान से यात्रा करते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी गोपनीय रखी जाती है कि बाहर से यह पता लगाना मुश्किल होता है कि राष्ट्रपति आखिर किस विमान में सवार हैं। हाल की रिपोर्टों में उनके विमान को 'फ्लाइंग क्रेमलिन' भी कहा गया है।इस यात्रा के दौरान खास बात यह रही कि पुतिन के साथ एक जैसा दूसरा विमान भी उड़ता दिखाई दिया।

दोनों का मॉडल, रंग और बाहरी डिजाइन एक जैसा था। यानी आसमान से देखने वाले के लिए दोनों में अंतर करना आसान नहीं था। यही पूरी सुरक्षा रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को से आईएल-96-300पीयू मॉडल के दो एक जैसे विमानों के साथ भारत के लिए उड़ान भरी। इनमें से

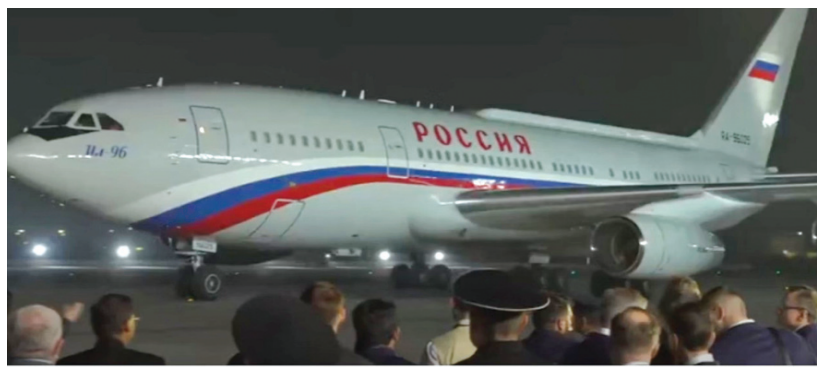

एक विमान में राष्ट्रपति होते हैं, जबकि दूसरा डिकॉय विमान के तौर पर साथ उड़ता है। इसका मकसद यह भ्रम बनाए रखना है कि पुतिन वास्तव में किस विमान में मौजूद हैं। दोनों विमान एक ही मॉडल के होते हैं और उनका रंग-रूप भी एक जैसा रखा जाता है, ताकि बाहर से पहचान करना मुश्किल रहे। दोनों विमान एक साथ उड़ान भरते हैं और पुतिन इनमें से किसी एक में होते हैं, लेकिन कौन से विमान में हैं, यह सार्वजनिक तौर पर पता नहीं चलता। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यही है कि किसी संभावित हमलावर के लिए पहले यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि राष्ट्रपति किस विमान में यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के विमान की वास्तविक पहचान की जानकारी उनकी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों तक ही सीमित रहती है।

क्या रडार पर भी दोनों विमानों को लेकर भ्रम पैदा किया जाता है- दी गई जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ दो एक जैसे विमान उड़ाने तक सीमित नहीं है। दोनों विमानों के रडार सिग्नल में भी समय-समय पर बदलाव होता है। कभी एक विमान का सिग्नल बंद दिखाई देता है तो कभी दूसरे का। कुछ समय के लिए दोनों विमान ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि केवल सार्वजनिक फ्लाइट ट्रैकिंग के आधार पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि पुतिन किस विमान में हैं।

कजाकिस्तान यात्रा में भी दिखी थी ऐसी ही रणनीति

कजाकिस्तान की यात्रा के दौरान दोनों विमानों को फ्लाइट ट्रैकर पर एक-दूसरे के बेहद करीब उड़ते देखा गया था। दोनों विमान लगभग एक ही गति से उड़ रहे थे, जिससे यह पहचानना और मुश्किल हो गया कि राष्ट्रपति किस विमान में हैं। उस समय दोनों विमानों की पहचान आरएसडी221 और आरएसडी369 के तौर पर हुई थी। इसके बावजूद सार्वजनिक ट्रैकिंग से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पुतिन इनमें से किस विमान में सवार थे। पुतिन का विमान आईएल-96-300पीयू सामान्य यात्री विमान का साधारण रूप नहीं है। यह आईएल-96-300 का विशेष रूप से तैयार किया गया संस्करण है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पीयू का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति के विशेष विमान के तौर पर होता है। इस विमान की सबसे महत्वपूर्ण खासियत उसकी सुरक्षित संचार व्यवस्था बताई जाती है। इसमें सैटेलाइट फोन और ऐसी विशेष संचार सुविधाओं का जिक्र है, जिनकी मदद से राष्ट्रपति यात्रा के दौरान भी रूस से संपर्क में रह सकते हैं। विमान को मिसाइल हमले से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा उपकरणों से लैस बताया गया है। इसी वजह से इसे आम राष्ट्रपति विमान से कहीं ज्यादा सुरक्षित और विशेष विमान माना जाता है। विमान में सैटेलाइट फोन और विशेष संचार व्यवस्था मौजूद होने की जानकारी दी गई है, ताकि यात्रा के दौरान भी संपर्क बना रहे। इसमें मिसाइल हमले से बचाने वाली विशेष सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र है, जो विमान की सुरक्षा को मजबूत बनाती है। इस विमान को रूस की परमाणु ताकत को नियंत्रित करने में सक्षम विशेष कमांड विमान के तौर पर भी बताया गया है।

संपादकीय | पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी की अगुआई में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने जिस तरह की बेलगाम कार्रवाई की थी, उस पर हर तरफ से तीखे सवाल उठे थे। यह भी कहा गया कि अगर विद्यार्थियों का अपने मुद्दों पर बात करना, सरकार से खामियों को दुरुस्त करने की मांग करना इतना मुश्किल है और इसके बदले उन्हें पुलिस की बेरहम कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, तो यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे के कितना अनुरूप है।

यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पर तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और मारपीट देखना बेहद दुखद है। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस अफसरों से अपेक्षित तटस्थता भी गायब होती दिख रही है। कायदे से पुलिस-प्रशासन और सरकार को अदालत की इस टिप्पणी पर गौर करते हुए अपने रवैये में सुधार करने की जरूरत थी। मगर शीर्ष अदालत की टिप्पणियों की पुलिस को कितनी फिक्र है, यह सिर्फ इतने से ही समझा सकता है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने को कारण बता कर विद्यार्थियों को नोटिस देना शुरू कर दिया गया है। जबकि इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट पुलिस के रवैये पर नाराजगी जता चुका है।

गौरतलब है कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में नोएडा की कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के एक छात्र के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया था। इस मसले पर सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ शब्दों

में कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के बावजूद मजिस्ट्रेट ने ऐसा नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। दरअसल, अदालत ने अपने पहले के आदेश में साफ तौर पर कहा था कि किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। जाहिर है, दिल्ली में प्रदर्शन और उसमें हुई कार्रवाई के संदर्भ में अदालत ने एक तरह से स्पष्ट लहजे में पुलिस और प्रशासन को एक बार फिर उसकी सीमा याद दिलाई है। हालांकि छात्र को जारी नोटिस बाद में वापस ले लिया गया, लेकिन यह विचित्र है कि नोएडा की कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह कार्रवाई करते हुए अदालत के निर्देश का खयाल रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अगर किसी छात्र को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है, इस दुस्साहस का स्रोत आखिर क्या है? क्या ऐसा परोक्ष रूप से सरकार के संरक्षण और निर्देश की वजह से किया जाता है? अगर ऐसा नहीं है, तो पुलिस या प्रशासन की नजर में शीर्ष अदालत के निर्देशों की क्या अहमियत है? यह समझना मुश्किल है कि जब पुलिस को किसी आंदोलन से निपटने के लिए तैनात किया जाता है, तो संवाद के जरिए समाधान की राह खोजने के बजाय कई बार वह बिना किसी हिचक के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अधिकतम बेरहम क्यों हो जाती है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बलप्रयोग या कार्रवाई की धमकी का सहारा लिया जाएगा, तो इसका देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर दूरगामी असर पड़ेगा। सरकार की ओर से हुई लापरवाही या उसकी किसी कमी पर सवाल उठाना या अपनी मांगों के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना आम नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। अभिव्यक्ति का यह अधिकार अगर सुरक्षित है, तो इसी से लोकतंत्र का जीवन बचेगा।

बिहार बाढ़: की विभीषिका: कुदरत का कहर या प्रशासनिक नाकामी?

बिहार हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका का सामना करता है। इसका मतलब यह होता है कि इसकी प्रकृति को समझ कर इससे बचाव के इंतजाम किए जा सकते हैं। मगर इतने वर्षों से अमूमन हर वर्ष बाढ़ की तबाही के बावजूद राज्य को इस प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए कभी ठोस उपाय नहीं किए गए। इस बार भी नदियां उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा की वजह से राज्य के चौदह जिलों में स्थिति गंभीर हो गई है। चालीस लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। राहत शिविरों की अपनी सीमा है। गौरतलब है कि हर साल नेपाल से आने वाली नदियां तबाही लेकर आती हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार इन नदियों के पानी को संभालने और आम लोगों को राहत के लिए कोई ठोस तंत्र विकसित नहीं कर पाई है। हर वर्ष बाढ़ राहत कार्यों पर निर्भरता

के बजाय अगर सरकार बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर ध्यान केंद्रित करती, तो इस समस्या को सुलझाने की दिशा में काफी आगे बढ़ा जा सकता था। नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए तटबंध आज नाकाम साबित हो रहे हैं, तो इस समस्या की जड़ में जाने की जरूरत है। यह निराशाजनक ही है कि हर साल बाढ़ राहत के नाम पर रस्मी कवायद कर अगले वर्ष फिर बाढ़ की प्रतीक्षा की जाती है। एक बड़ी चुनौती यह है कि हिमालयी नदियां हर बार अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती हैं, जो राज्य की नदियों में जमा होती जाती हैं। नतीजा यह कि उथली हो रही नदियों का पानी रिहाइशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लेता है। सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया होता, तो राज्य में जल प्रबंधन की नई तस्वीर बन सकती थी। यह बेवजह नहीं है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को इस आपदा से सबसे अधिक नुकसान होता है। सही है कि बाढ़ को रोका नहीं जा सकता, लेकिन धरातल पर योजनाओं को साकार कर जन-जीवन को व्यापक नुकसान से जरूर बचाया जा सकता है।

आज का कार्टून

नशे की गिरफ्त में भारत: युवाओं पर सबसे बड़ा संकट

करोड़ों लोग कर रहे ड्रग्स का इस्तेमाल

> जब तक समाज के भीतर से नशीले पदार्थों की मांग समाप्त नहीं होगी, यह जंग अधूरी रहेगी। हमें 'जेल नहीं, इलाज' और 'सहानुभूति, न कि तिरस्कार' के सिद्धांत को अपनाना होगा। उत्तराखंड के देहरादून में एक गांव की महिलाओं ने जिस तरह मोर्चा थामा है, वह काबिले-तारीफ है। प्राथमिक स्तर पर ही स्कूलों और कालेजों में नियमित जांच और पेशेवर काउंसलरों की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए। खेलकूद, कला और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना आवश्यक है। सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका परिवार की है। माता-पिता को अपने बच्चों के साथ भावनात्मक संवाद स्थापित करना होगा, ताकि बच्चे तनाव के क्षणों में मादक पदार्थ के बजाय परिवार का सहारा लें। सरकार, नागरिक समाज, मीडिया और परिवारों को एकजुट होकर 'नशे के विरुद्ध और जिंदगी को हां' का नारा बुलंद करना होगा।

प्रमोद कुमार वाजपेयी

उस व्यक्ति की त्रासदी का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है, जिसका बेटा नशे का आदी हो चुका है। इसी वजह से उसकी पढ़ाई छूट चुकी है और अब वह दिन भर कंप्यूटर गेम खेलता रहता है या दिन भर ट्रक के अड्डे पर जुआ खेलता रहता है।

पिता इसलिए परेशान हैं कि वह अब उसके मादक पदार्थों पर भी हाथ साफ करने लगा है और उसे अपने बेटे के भविष्य का अनुमान है और अब वह इसी को लेकर फिक्रमंद है। हालांकि खुद पचास का पिता भी नशे के जाल में इस कदर फंसा हुआ है, उसके हाथ कांपने लगे हैं और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है।

बीते कुछ महीने के भीतर ऐसे मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। जिनका नशे की लत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वैसे लोग अब परामर्श और आपात हस्तक्षेप तक के लिए मनोचिकित्सकों या काउंसलरों के पास पहुंचने लगे हैं। संकट की भयावहता के चलते केंद्र सरकार अब नशा मुक्त भारत अभियान की बात कर रही है और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नशाखोरी के विरुद्ध बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे हैं।

युवाओं को शपथ दिलवाया जा रहा है, स्कूल-कालेजों को नशे के विरुद्ध माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त किया जा रहा है तथा बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मगर इसी बीच यह खबर भी आती है कि पंजाब में एक ग्रामीण ने जब मादक पदार्थों की धड़ल्ले से आपूर्ति पर सवाल उठाया, तो उसे प्रताड़ित किया गया और आखिर उसने आत्महत्या कर ली।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एम्स के 'नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर' के सहयोग से जारी की गई आधिकारिक रिपोर्ट 'मैग्नीट्यूड आफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया' के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री और नशे की समस्या अब केवल कुछ महानगरों या सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही। यह एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल और सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 10 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के बीच लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनमें से 5.7 करोड़ से अधिक लोगों को तत्काल चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता है। वहीं, लगभग 3.1 करोड़ लोग भांग, गांजा या चरस जैसे कैनबिस उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति ओपियोइड्स (अफीम, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स) के मामले में है।

भारत में ओपियोइड का उपयोग वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना अधिक है। देश में करीब 2.26 करोड़ ओपियोइड उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से साठ लाख से अधिक लोग इस लत के गंभीर दुश्चक्र में फंस चुके हैं। इससे भी अधिक विचलित करने वाला तथ्य यह है कि देश के लगभग 1.7 फीसद बच्चे और किशोर (यानी करीब अठारह लाख बच्चे) 'इन्हेलेंट्स' यानी सूंघने वाले नशे जैसे थिनर, फ्लूइड, सरेष आदि के जाल में फंस चुके हैं।

हाल के वर्षों में एमडीएमए, मेथमफेटामाइन और अवैध दवाओं (सिंथेटिक ओपियोइड्स) की मांग और जब्ती में आया भारी उछाल यह साबित करता है कि नशे का बाजार अब पारंपरिक से बदलकर अत्यधिक घातक रासायनिक स्वरूप अख्तियार कर चुका है। मादक पदार्थों की यह विभीषिका पूरे देश में फैली है, लेकिन भौगोलिक और सामरिक कारणों से कुछ राज्य इसके गढ़ बन गए हैं।

मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर जैसे उत्तर-पूर्वी राज्य ओपियोइड और नशीली दवाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दूसरी ओर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सिंथेटिक मादक पदार्थों और हेरोइन का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। दरअसल, भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच फंसा हुआ है। इसके पश्चिम में 'गोल्डन क्रिसेंट' (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान) है और पूर्व में 'गोल्डन ट्रायंगल' (म्यांमार, लाओस और थाईलैंड) है।

इससे भारत न केवल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक प्रमुख 'ट्रांजिट रूट' बना, बल्कि धीरे-धीरे एक विशाल उपभोक्ता बाजार में भी तब्दील हो गया। वर्तमान में डार्कवेब, क्रिप्टोकरेंसी और ड्रोन तकनीक के माध्यम से होने वाली उच्च-तकनीक तस्करी के संजाल ने इस चुनौती को कई गुना बढ़ा दिया है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति को केवल एक 'अपराधी' या 'चरित्रहीन' के चश्मे से देखना हमारी भूल होगी। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मादक पदार्थों या ड्रग की लत एक मानसिक बीमारी है।

शुरुआत में युवा वर्ग गलाकाट प्रतिस्पर्धा, करिअर की अनिश्चितता, बेरोजगारी जनित अवसाद या सहकर्मियों के दबाव के कारण अनजाने में इस दलदल में कदम रखता है, लेकिन धीरे-धीरे रासायनिक निर्भरता के कारण व्यक्ति का अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति इस लत से बाहर निकलना चाहता है, तो सबसे बड़ी बाधा 'विड्राल सिम्प्टम्स' यानी तड़प और शारीरिक कष्ट तथा समाज में व्याप्त 'सामाजिक लांछन' बनते हैं। सामाजिक बहिष्कार के डर से पीड़ित या उसका परिवार समय पर मदद मांगने या नशामुक्ति केंद्र जाने से कतराता है।

परिणामतः यह समस्या बंद कमरों के भीतर ही सुलगती रहती है और आखिरकार आत्महत्या या गंभीर अपराधों के रूप में सामने आती है। महंगी लत को पूरा करने के लिए युवा वर्ग चोरी, झपटमारी और यहां तक कि जघन्य अपराधों की राह पकड़ लेता है। इस महामारी से निपटने के लिए वर्तमान में आपूर्ति, मांग और नुकसान में कमी की त्रिआयामी रणनीति पर काम किया जा रहा है। एक ओर कड़े एनडीपीएस अधिनियम के तहत तस्करों की गिरफ्तारियां कर संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, तो दूसरी ओर देश में सरकारी ओर मान्यता प्राप्त नशामुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ा कर 780 से अधिक की गई है, जिनके माध्यम से 8.20 लाख से अधिक लोगों को इलाज और पुनर्वास का लाभ मिल चुका है। मगर कड़े कानूनों और पुलिसिया कार्रवाइयों की अपनी एक सीमा है। वे केवल आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं।

जब तक समाज के भीतर से नशीले पदार्थों की मांग समाप्त नहीं होगी, यह जंग अधूरी रहेगी। हमें 'जेल नहीं, इलाज' और 'सहानुभूति, न कि तिरस्कार' के सिद्धांत को अपनाना होगा। उत्तराखंड के देहरादून में एक गांव की महिलाओं ने जिस तरह मोर्चा थामा है, वह काबिले-तारीफ है। प्राथमिक स्तर पर ही स्कूलों और कालेजों में नियमित जांच और पेशेवर काउंसलरों की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए।

खेलकूद, कला और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना आवश्यक है। सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका परिवार की है। माता-पिता को अपने बच्चों के साथ भावनात्मक संवाद स्थापित करना होगा, ताकि बच्चे तनाव के क्षणों में मादक पदार्थ के बजाय परिवार का सहारा लें। सरकार, नागरिक समाज, मीडिया और परिवारों को एकजुट होकर 'नशे के विरुद्ध और जिंदगी को हां' का नारा बुलंद करना होगा। एक नशामुक्त, स्वस्थ और मानसिक रूप से सुदृढ़ युवा पीढ़ी ही सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक नींव बन सकती है।

बच्चों को बेहतर जिंदगी देने की चाह में छोटा हुआ परिवार

> आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे बच्चे भी अपने माता-पिता को रोज देख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई देने वाला चेहरा और सामने बैठा हुआ व्यक्ति एक जैसा अनुभव नहीं देते। शायद इसलिए संपर्क बढ़ने के बावजूद अकेलापन हमेशा कम नहीं हुआ है। एकल-संतान परिवारों के संदर्भ में यह बात और महत्त्वपूर्ण हो जाती है। एक बच्चे के लिए माता-पिता बहुत कुछ कर पाते हैं। अपनी आय, समय और ध्यान का बड़ा हिस्सा उसी पर लगा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वही बच्चा अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाए, तो माता-पिता के पास अपने भावनात्मक संसार को साझा करने वाले लोग भी कम हो सकते हैं।

श्याम यादव

माता-पिता जब बच्चे को बड़ा करते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आगे चलकर बच्चा उनके लिए क्या करेगा। उनकी चिंता यह होती है कि बच्चे को वह सब मिल जाए, जो वे उसे देना चाहते हैं। जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिलीं, वे बच्चे को मिलें। जिस रास्ते पर उन्हें मुश्किलें आईं, बच्चे के लिए वह रास्ता कुछ आसान हो। शायद इसी इच्छा ने परिवारों की सोच भी बदली है। दो बच्चों के छोटे परिवार के बाद अब एक-संतान परिवार की धारणा भी इसी बदलाव का हिस्सा है। एक बच्चा हो, तो उसकी पढ़ाई-लिखाई पर अधिक खर्च किया जा सकता है, उसकी पसंद और जरूरतों को समझने के लिए अधिक समय दिया जा सकता है और उसके बेहतर भविष्य की तैयारी की जा सकती है।

एक बच्चे को अधिक अवसर देने की इच्छा आज बहुत-से माता-पिता के फैसलों में दिखाई देती है। इसमें कुछ अस्वाभाविक भी नहीं है। मगर सवाल यह है कि परिवार छोटा होने के साथ क्या बच्चे का अपना संसार भी कुछ छोटा हो जाता है? एक समय घर में भाई-बहन होते थे और रिश्तेदारों की आवाजाही भी बनी रहती थी।

दादा-दादी के पास बैठना, चाचा-चाची से झगड़ना, मामा-मौसी के घर जाना- इन सबका अपना महत्त्व था। बच्चा इन्हीं संबंधों के बीच बड़ा होता था। उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगता था कि हर बात अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती। कभी किसी की सुननी पड़ती थी, कभी अपनी चीज बांटनी पड़ती थी और कभी बिना किसी खास कारण के किसी के काम आना पड़ता था। एक बच्चे वाले परिवार में माता-पिता का ध्यान स्वाभाविक रूप से उसी पर अधिक रहता है। उसकी पढ़ाई, स्वास्थ्य, पसंद और भविष्य घर की बातचीत का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। कभी-कभी माता-पिता अपनी अधूरी इच्छाओं को भी बच्चे के भविष्य से जोड़ देते हैं। बच्चा सफल होता है तो लगता है जैसे उनकी मेहनत सफल हुई। फिर वही बच्चा बड़ा होकर अपनी राह पर निकलता है। पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, नौकरी दूसरे शहर में मिलती है और फिर अपनी गृहस्थी तथा जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाता है। माता-पिता उसके आगे बढ़ने से खुश होते हैं। आखिर उन्होंने उसे रोकने के लिए तो नहीं पाला था! बच्चों की जिंदगी जितनी फैलती जाती है, कई बार माता-पिता का संसार उतना ही सिमटता जाता है।

फोन है, वीडियो काल है, कभी त्योहार पर मुलाकात हो जाती है। जरूरत हो, तो पैसे भेज दिए जाते हैं। बीमारी में डाक्टर से सलाह भी मिल जाती है। बहुत-सी चीजें आसान हुई हैं। फिर भी उम्र के एक पड़ाव पर शायद इंसान को केवल सुविधा नहीं, किसी अपने की मौजूदगी की जरूरत भी होती है। हाल में एक बुजुर्ग पिता की मृत्यु से जुड़ी एक घटना सामने आई।

उनकी संतानें अपने-अपने जीवन में दूर थीं और अंतिम समय में उनके पास पहुंच पाना संभव नहीं हुआ। आर्थिक मदद और वीडियो काल के जरिए अंतिम विदाई की बात सामने आई। यह घटना एक सवाल छोड़ती है कि क्या रिश्तों की जगह धीरे-धीरे व्यवस्थाएं ले रही हैं? किसी बुजुर्ग की दवा का इंतजाम किया जा सकता है। पैसे भेजे जा सकते हैं।

किसी देखभाल करने वाले को रखा जा सकता है। यह सब जरूरी भी है, लेकिन इन सबके बीच वह व्यक्ति कहां है, जो उसके पास बैठकर उसकी बात सुन सके? बीमारी का खर्च उठाना और बीमारी के समय पास बैठना एक ही बात नहीं है। तकनीक ने दूरियों को कम करने में बहुत मदद की है। आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे बच्चे भी अपने माता-पिता को रोज देख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई देने वाला चेहरा और सामने बैठा हुआ व्यक्ति एक जैसा अनुभव नहीं देते। शायद इसलिए संपर्क बढ़ने के बावजूद अकेलापन हमेशा कम नहीं हुआ है। एकल-संतान परिवारों के संदर्भ में यह बात और महत्त्वपूर्ण हो जाती है। एक बच्चे के लिए माता-पिता बहुत कुछ कर पाते हैं। अपनी आय, समय और ध्यान का बड़ा हिस्सा उसी पर लगा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वही बच्चा अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाए, तो माता-पिता के पास अपने भावनात्मक संसार को साझा करने वाले लोग भी कम हो सकते हैं। यह एक बच्चे के होने की समस्या नहीं, बल्कि छोटे होते पारिवारिक दायरे की एक चुनौती है।जीवन बदल चुका है। लोगों के रहने और काम करने के तरीके बदल गए हैं। मगर रिश्तों का अर्थ शायद इतना नहीं बदला है कि उनमें उपस्थिति की जरूरत ही न रहे। माता-पिता अगर बच्चे को अपना पूरा संसार बना लें, तो उसके दूर जाने पर उनका अकेलापन बढ़ सकता है। उम्र के साथ अपने मित्रों, रुचियों और सामाजिक जीवन को बनाए रखना भी जरूरी है। परिवार जीवन का बड़ा हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। फिर भी बच्चे को स्वतंत्र बनाना और उसे रिश्तों से मुक्त कर देना- इन दोनों में फर्क है।

उसे अच्छी शिक्षा देना जितना जरूरी है, उतना ही यह समझ देना भी जरूरी है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिन्हें सुविधा के हिसाब से नहीं निभाया जाता। परिवार छोटा होना कोई समस्या नहीं। सवाल बस इतना है कि क्या परिवार के छोटा होने के साथ हमारी दुनिया भी इतनी छोटी हो गई है कि उसमें माता-पिता के लिए जगह निकालना मुश्किल पड़ने लगे? हमने अपने बच्चे को ज्यादा देने के लिए परिवार छोटा किया। शायद अब यह सोचने की बारी है कि हमने उसे दूसरों के लिए जगह बनाना कितना सिखाया। माता-पिता को अपने बच्चों से कोई प्रतिदान नहीं चाहिए। वे चाहते हैं कि बच्चा अपनी दुनिया बनाए, आगे बढ़े और खुश रहे। बस इतना कि उस दुनिया में उनके लिए कोई कोना ऐसा हो, जहां उम्र बढ़ने पर भी उन्हें अपने होने का एहसास बना रहे। आखिर परिवार छोटा करना हमारी पसंद हो सकती है, लेकिन रिश्तों को छोटा करना हमारी मजबूरी नहीं होना चाहिए।

सार-समाचार

महिला टी20 सीरीज - साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिम्बाब्वे की 17 सदस्यीय टीम घोषित

कप्तान नकोमो की वापसी

हरारे, । साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे की महिला टीम को बड़ी राहत मिली है । जोसेफिन नकोमो फिट होकर टीम की कमान संभालने के लिए वापस आ गई हैं । इस सीरीज के पांच मुकाबले 11, 13, 15, 17 और 19 सितंबर को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे । जोसेफिन नकोमो चोट के कारण मई में पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल दौरे पर नहीं जा सकी थीं, लेकिन तीन महीनों में वह अच्छी तरह से ठीक हो गई हैं और 17 सदस्यों वाली टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं । उनके साथ अनुभवी बल्लेबाज शार्ने मेयर्स ने 2 साल तक बाहर रहने के बाद टीम में वापसी की है । मेयर्स अब तक 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं ।

ऑलराउंडर न्याशा ग्वानजुरा ने भी टीम में वापसी की है, जबकि टीम की अनुभवी सदस्य, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, मोडेस्टर मुपाचिकवा, लोरेन त्सुमा और लोरिन फिरी ने पाकिस्तान सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के चलते अपनी जगह बरकरार रखी है । जिम्बाब्वे की टीम में ऐसे तीन खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते आईसीसी अंडर-19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालीफायर डिवीजन 1 में जिम्बाब्वे के लिए खेला था । इनमें कप्तान लोरेन पेम्हिवा, बिलव्ड बिजा और क्रिस्टीना मुतासा हैं, जिन्हें अब बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा । जिम्बाब्वे सितंबर और अक्टूबर 2025 में क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में एक द्विपक्षीय सीरीज में यूनाइटेड अरब अमीरात की मेजबानी करने के बाद पहली बार अपने घरेलू मैदान पर वापसी करेगा ।

जिम्बाब्वे की टीम : जोसेफिन नकोमो (कप्तान), बिलव्ड बिजा, कुदजई चिगोरा, फ्रांसेस्का चिपारे, न्याशा ग्वानजुरा, लिंडोकुहले मभेरा, तेंदई मकुशा, मिशेल मावुंगा, शार्ने मेयर्स, मोडेस्टर मुपाचिकवा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, क्रिस्टीना मुतासा, केलिस नधलोवु, लोरेन पेम्हिवा, लोरिन फिरी, नोमवेलो सिबांडा, लोरेन त्सुमा ।

मुरली कार्तिक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार जीत के नायक, नहीं मिल सके पर्याप्त मौके, कैरियर रहा छोटा

नई दिल्ली । टीम इंडिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज मुरली कार्तिक का करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा । कार्तिक वानखेड़े के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली यादगार जीत के नायक रहे । हालांकि, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले के टीम में होने के कारण उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा मौके नहीं मिले । मुरली कार्तिक का जन्म 11 सितंबर, 1976 को चेन्नई में हुआ । कार्तिक के परिवार में पढ़ाई को काफी महत्व दिया जाता था । हालांकि, उनका बचपन से क्रिकेट से खास लगाव हो गया था । 12 साल की उम्र में ही कार्तिक ने इस खेल में अपना करियर बनाने की ठान ली थी । क्रिकेट के साथ-साथ कार्तिक पढ़ाई में भी अच्छे थे । उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से वाणिज्य में ग्रेजुएशन की । कार्तिक ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू साल 1996 में किया । घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार

प्रदर्शन के बूते जल्द ही वह सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे । साल 2000 में मुरली कार्तिक को भारत की जर्सी में अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने को मिला । डेब्यू टेस्ट मैच में कार्तिक ने 3 विकेट निकाले । इसके बाद उन्होंने साल 2002 में वनडे क्रिकेट में अपना डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ किया ।

मुरली कार्तिक ने भारत के लिए कुल 8 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान उन्होंने 24 विकेट अपने नाम किए । कार्तिक ने साल 2004 में वानखेड़े के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई । कार्तिक ने पहली पारी में 4 और दूसरी में 3 विकेट लेते हुए भारत को रोमांचक से भरे मुकाबले में 13 रनों से जीत दिलाई । इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 93 रन बनाकर ऑलआउट हुई ।

हालांकि, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जैसे दिग्गज गेंदबाजों के टीम में होने की वजह कार्तिक को क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में ज्यादा मौके नहीं मिले । मुरली ने कुल 37 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया । इस दौरान उन्होंने 5.07 की इकोनॉमी से 37 विकेट चटकाए ।

डीडीसीए ने की पुष्टि

दिल्ली पुलिस की गुजारिश के बावजूद

13 को ही होगा पहला टी20 मैच

भारत बनाम अफगानिस्तान

नई दिल्ली । भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला तय कार्यक्रम के हिसाब से 13 सितंबर को ही खेला जाएगा । दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने इस बात की पुष्टि की है । दरअसल, भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले टी20 मुकाबले को लेकर दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ को पत्र लिखकर इस मैच को किसी और दिन कराने की मांग की थी । दिल्ली में 11 से 13 तारीख तक ब्रिक्स सम्मेलन होना है, जिसके चलते वीवीआईपी रूट की व्यवस्था रहेगी । मैच में 20 से 25 हजार फैंस के आने की संभावना है, ऐसे में डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दिल्ली पुलिस के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराना मुश्किल होगा । हालांकि, डीडीसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया, 'अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर को होने वाला भारत-अफगानिस्तान का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा । दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक के बाद डीडीसीए को सभी जरूरी मदद और इंतजामों का भरोसा दिलाया गया है । मैच स्थगित नहीं होगा ।'

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाने हैं । इस बार सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है । अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई की तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है । सीरीज का दूसरा मुकाबला 15 और अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाना है ।

गुरुवार को बीसीसीआई ने बताया कि हर्षित राणा जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 से भी बाहर हो गए हैं । हर्षित की जगह पर भारतीय टीम में तेज गेंदबाज यश ठाकुर को शामिल किया गया है । यश जिम्बाब्वे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे और उन्होंने 2 मैचों में 4 विकेट चटकाए थे ।

ब्रेक ने मेरी गेंदबाजी को प्रभावित किया

दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद मोहम्मद सिराज का बयान

चेन्नई । दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन और तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया । ईस्ट जोन विजेता रही । साउथ जोन की तरफ से खेल रहे भारतीय टीम के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में प्रभावी नहीं रहे । मोहम्मद सिराज ने मैच में कुल 41 ओवर गेंदबाजी की और महज 1 विकेट ले पाए । इस दौरान उन्होंने 187

रन लुटाए । सिराज के गेंदों की गति भी 125-130 किलोमीटर/घंटा के बीच रही । भारतीय टेस्ट टीम के नियमित और प्रभावी तेज गेंदबाज सिराज का यह प्रदर्शन निराशाजनक और क्रिकेट विश्लेषकों और फैंस के लिए चौंकाने वाला था । सिराज का मानना है कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले उनको मिले 2 महीने के ब्रेक ने उनकी गेंदबाजी को प्रभावित किया है । इसी वजह से श्रीलंका सीरीज के दौरान गाले और कोलंबो में हुए टेस्ट मैचों में उनकी गेंदबाजी की गति भी कम रही ।

दलीप ट्रॉफी फाइनल की समाप्ति के बाद सिराज ने कहा, 'मैं पूरी तरह से एक रिदम गेंदबाज हूं । अगर मैं अपने रंग में नहीं हूं, तो मैं क्रीज से तेजी से नहीं निकल सकता । श्रीलंका में यही मुश्किल थी - मेरा रन-अप बिखरा हुआ लग रहा था । कुछ स्ट्राइड बहुत छोटे थे, कुछ बहुत लंबे, और इससे मेरा फ्लो टूट गया । इससे मेरी गति पर असर पड़ा ।'

सिराज ने कहा, 'हर गेंदबाज का शरीर अलग होता है । मेरा शरीर लंबे ब्रेक को अच्छी तरह नहीं झेल पाता । छोटा ब्रेक ठीक है । दस साल के करियर में, मैंने कभी पूरे दो महीने की छुट्टी नहीं ली थी । मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था और कभी-कभी गेंदबाजी भी कर रहा था, लेकिन कितना भी अभ्यास कर लो, मैच वाली स्थिति नहीं बनती । यह एक नया अनुभव था । यह मेरे आगे के करियर के लिए बेहद अहम था ।'

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा, 'हम सीधे श्रीलंका से आए थे, जहां हमने दूसरे टेस्ट में साढ़े तीन दिन फील्डिंग की, और एक सप्ताह के अंदर, हम यहां चेन्नई की चिलचिलाती गर्मी में खेल रहे थे । यह पैशन पर निर्भर है । जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो आप बहाने नहीं बना सकते । आपको अपनी टीम और देश के लिए पूरी कोशिश करनी होती है । मुझे विकेट नहीं मिला, लेकिन यह अनुभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम आएगा ।' सिराज की गेंदबाजी पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी में बेहतर रही ।

उन्होंने कहा, 'पहली पारी में, पिच फ्रेश लग रही थी, इसलिए मैंने बहुत तेज गेंदबाजी करने की कोशिश की ।

शेफाली की फिफ्टी, दीप्ति-नंदिनी ने मिलकर चटकाए 5 विकेट

बांग्लादेश को हराकर फाइनल में भारत

दुबई । भारत ने गुरुवार को विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल-1 में बांग्लादेश को 40 रन से मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां 13 सितंबर को उसका सामना पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल-2 की विजेता टीम

से होगा । गुरुवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 149 रन बनाए । टीम ने महज 9 के स्कोर पर स्मृति मंधाना (2) का विकेट गंवा दिया था । इसके बाद प्रतिका रावल ने शेफाली वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 50 रन जुटाकर टीम को मजबूती दी । प्रतिका टीम के खाते में 20 रन जोड़कर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' शेफाली वर्मा (40 गेंदों में 64 रन) के साथ 33 रन और ऋचा घोष (21) के साथ 36 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया ।

इसके अलावा, कौर ने दीप्ति शर्मा (13) के साथ पांचवें विकेट के लिए 8 गेंदों में 21 रन जुटाए । कप्तान 28 गेंदों में 2 छक्कों के साथ 24 रन बनाकर नाबाद रहीं । विपक्षी खेमे से सुल्ताना खातून ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि मारूफा अख्तर, नाहिदा अख्तर और राबिया खान ने ने 1-1 विकेट चटकाया ।

इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 109 रन ही बना सकी । दिलारा अख्तर ने जुवैरिया फिरदौस के साथ पहले विकेट के लिए 33 गेंदों में 26 रन जोड़े । फिरदौस 14 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद शोभना मोस्तरी (18) ने कप्तान निगार सुल्ताना (19) के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 रन जोड़कर टीम को 66 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद बांग्लादेशी टीम बिखर गई ।

बांग्लादेश के खिलाफ शांत रहते हुए पारी को बढ़ाने की कोशिश की: शेफाली वर्मा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है । गुरुवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई । भारतीय टीम की जीत में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की 64 रनों की विस्फोटक पारी की अहम भूमिका रही ।

शेफाली को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया । वर्मा ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को यहां महिला एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जिताने वाली 64 रन की पारी के दौरान मुश्किल बैटिंग पिच के हिसाब से खुद को ढालते हुए शांत रहने और टीम के लिए योगदान देने पर ध्यान दिया ।

यूएस ओपन: सबालेंका ने पेगुला को हराकर फाइनल में जगह बनाई

लगातार तीसरे खिताब से एक जीत दूर

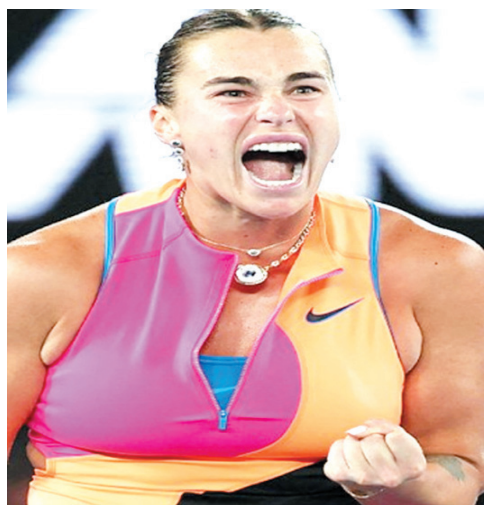

न्यूयॉर्क । टॉप सीड एरिना सबालेंका लगातार तीसरा यूएस ओपन खिताब जीतने से मात्र एक जीत दूर हैं । टॉप सीड एरिना सबालेंका ने सेमीफाइनल में तीसरी सीड अमेरिकी जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में हराकर यूएस ओपन 2026 के महिला एकल के फाइनल में जगह बना ली है । आर्थर ऐश स्टेडियम कोर्ट पर खेले गए मुकाबले में एरिना सबालेंका ने जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की । सबालेंका ने अपने शानदार सर्विस गेम और जबरदस्त ग्राउंडस्ट्रोक से पेगुला को कभी भी मुकाबले में आने ही नहीं दिया । हार के साथ ही पेगुला का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया । पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों ने ज्यादा कुछ नहीं दिया, शानदार सर्व करते हुए मैच को 12वें गेम तक सर्व पर बनाए रखा, जिसमें सबालेंका 6-5 से आगे थीं । सबालेंका के जोरदार ग्राउंडस्ट्रोक के बाद पेगुला 0-40 से पीछे हो गईं और अंततः पहला सेट एरिना के नाम रहा । उन्होंने दूसरे सेट में भी मोमेंटम बनाए रखा, पेगुला के संदिग्ध दूसरे सर्व पर अटैक किया और कॉर्नर में लेजर फोरहैंड मारकर 3-1 की बढ़त के लिए जरूरी ब्रेक हासिल किया ।

आठवें गेम तक बाकी सेट सर्व पर ही चला, जब पेगुला ने मैच पॉइंट देने के लिए लंबा रिटर्न मारा । सबालेंका ने एक और जबरदस्त फोरहैंड मारकर जीत पक्की कर दी । साबालेंका ने अपनी जीत में सात एस और 29 विनर लगाए ।

राजीव राम ने पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में हार के बाद लिया संन्यास

न्यूयॉर्क । पूर्व डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 राजीव राम ने टेनिस को अलविदा कह दिया है । राम और जो सैलिसबरी की जोड़ी को छठी सीड वाली जर्मन जोड़ी ने यूएस ओपन 2026 के डबल्स के सेमीफाइनल में हराया । इस हार के साथ ही राजीव राम ने टेनिस को अलविदा कहा । 2021 से 2023 तक हर साल यूएस ओपन डबल्स का खिताब जीतने वाली राम और सैलिसबरी की जोड़ी को केविन क्राविएट्ज और टिम पुएट्ज से 6-3, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा । यूएसटीए के सीईओ क्रेग टिली और यूएस ओपन टूर्नामेंट के निदेशक एरिक बुटोरैक ने राजीव राम को उनके बेहतरीन करियर के लिए बधाई दी । बता दें कि

टिली, इलिनोइस यूनिवर्सिटी में राम के कॉलेज कोच हैं, जबकि एरिक उनके पूर्व डबल्स पार्टनर रहे हैं ।

राम और उनके लंबे समय के डबल्स पार्टनर सैलिसबरी टूर्नामेंट के इतिहास में अकेले ऐसे जोड़ी हैं जिन्होंने मेन्स डबल्स में तीन बार जीत हासिल की है । इंडियाना के रहने वाले राम ने लगातार 26 बार यूएस ओपन पुरुष डबल्स खेला है । यह अपने आप में ऐतिहासिक है । राजीव राम ने सेमीफाइनल के बाद कहा, 'वह इस खेल को अलविदा कहने का इससे बेहतर तरीका सोच भी नहीं सकते थे ।'

यूएसओपन.ओआरजी से बात करते हुए राजीव राम ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था । मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरी मां वहां थीं ।

सबालेंका के खिलाफ फाइनल में पूरी ऊर्जा के साथ उतरना होगा: एलेना

न्यूयॉर्क । यूएस ओपन 2026 महिला एकल का फाइनल दुनिया की नंबर 1 एलेना रायबाकिना और नंबर 2 एरिना सबालेंका के बीच रविवार (आईएसटी के मुताबिक) को होना है । रायबाकिना पहली बार फाइनल में पहुंची हैं, जबकि सबालेंका लगातार अपना तीसरा यूएस ओपन खिताब जीतने की कोशिश में हैं । सेमीफाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबालेंका के साथ होने वाले फाइनल को लेकर रायबाकिना ने कहा, 'मुझे सबालेंका के खिलाफ

अपनी पूरी ऊर्जा लगानी होगी । हम कई बार खेले हैं । हमने पहले भी अभ्यास किया है । वह बहुत आक्रामक खिलाड़ी हैं ।' उन्होंने कहा, 'उनके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से खेलना मुश्किल है । उनका गेम बड़ा है, सर्व बड़ा है, और मुझे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आना होगा । एरिना के खिलाफ अपनी बेस्ट सर्व लानी होगी और सही समय पर सही फैसले लेने होंगे क्योंकि ज्यादातर समय स्कोर टाइट होता है और यहीं पर फैसले से फर्क पड़ता है । हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी ।'

बायर्न ने चैंपियंस लीग के पहले मैच में बोडो/ग्लिम्ट को 5-0 से हराया

बर्लिन । जमाल मुसियाला ने बायर्न म्यूनिख की शुरुआती लाइनअप में वापसी करते हुए पहला गोल किया । इसकी मदद से जर्मन टीम ने यूईएफए चैंपियंस लीग में बोडो/ग्लिम्ट को 5-0 से हरा दिया । बायर्न ने शुरू से ही गेंद पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन शुरुआत में मेहमान टीम की पांच लोगों की डिफेंसिव लाइन को तोड़ने में संघर्ष किया । लुइस डियाज को पांच मिनट बाद पहला हाफ में मौका मिला, जोशुआ किमिच के क्रॉस पर उन्होंने पास से हेडर मारा, लेकिन गोलकीपर निकिता हाइकिन ने उसे बचा लिया । किमिच का 22 मीटर का शॉट 33वें मिनट में पोस्ट के बाहर लगा, इससे पहले हाइकिन ने पहले हाफ के आखिर में मुसियाला और फिर किमिच को रोका । हाइकिन, जिन्हें बाद

में सेव करते समय कमर में दिक्कत हुई, उनकी जगह हाफटाइम में जूलियन फे लुंड ने ले ली, और बायर्न को रीस्टार्ट के बाद सिर्फ दो मिनट में ही बढ़त मिल गई । हैरी केन को रोकने की कोशिश में व ब्लॉक हो गई, लेकिन मुसियाला ने लूज बॉल को पकड़ा और अपना शॉट बाएं कोने में मार दिया । केन ने 61वें मिनट में माइकल ओलिस की फ्री-किक डिलीवरी पर फे लुंड के पास से हेडर मारकर बढ़त दोगुनी कर दी । अल्फांसो डेविस ने 77वें मिनट में 17-मीटर का स्ट्राइक करके मैच को आसानी से खत्म कर दिया, जिसके छह मिनट बाद ओलिस ने लेनार्ट कार्ल के पास पर बायर्न के लिए चौथा गोल किया ।

डब्ल्यूबीबीएल सीजन 12: एडिलेड स्ट्राइकर्स में लौटीं सोफी एक्लेस्टोन, ऐसा रहा इनका रिकॉर्ड

एडिलेड । इंग्लैंड की स्टार खिलाड़ी सोफी एक्लेस्टोन विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) सीजन 12 के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स में वापसी करेंगी । 27 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर ने पिछले सीजन में स्ट्राइकर्स के लिए डेब्यू किया था और वह एक बार फिर टीम की बॉलिंग लाइन-अप में अनुभव और गुणवत्ता जोड़ेंगी । विमेंस बिग बैश लीग का आगामी सीजन 29 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच खेला जाएगा । पहले मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर्स की टीमें आमने-सामने होंगी । एडिलेड स्ट्राइकर्स 31 अक्टूबर को कैरन रोल्टन ओवल में मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी ।

एक्लेस्टोन ने एडिलेड स्ट्राइकर्स में वापसी पर खुशी जताते हुए कहा, 'मैं टीम के साथ दोबारा जुड़ने और पिछले सीजन में हासिल की गई कामयाबियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्साहित हूं । हम अगला कदम उठाने और फाइनल में जगह बनाने की कोशिश के लिए खुद को मजबूत स्थिति में लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ।

'स्ट्राइकर्स के कोच ल्यूक विलियम्स ने कहा कि एक्लेस्टोन की वापसी से टीम को बहुत मजबूती मिलेगी । विलियम्स ने कहा, 'सोफी एक वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी हैं । उनका हुनर, अनुभव और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत उन्हें हमारी टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बनाती है ।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए न्यायाधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा । पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार । **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यालय नं.0651-2253830, मो.9471717919, 7895244551 ईमेलः alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013) 66670